My Notes
राष्ट्रीय

इसरो ने एक और रिकॉर्ड के साथ इतिहास रचा:

104 सैटलाइट्स को एकसाथ छोड़कर इसरो ने एक और रेकॉर्ड बनाते हुए इतिहास रच दिया। आंध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से एक ही रॉकेट से अंतरिक्ष में 104 सैटलाइट्स और एक रॉकेट छोड़कर इसरो ने रूस को पछाड़ दिया। अभी तक एक साथ सबसे ज्यादा (37) सैटलाइट्स छोड़ने का रेकॉर्ड रूस के नाम था। अमेरिका एक साथ 29 सैटलाइट्स लॉन्च कर चुका है। पीएसएलवी-सी37 कार्टोसैट-2 सीरीज सैटलाइट मिशन को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। ये सैटलाइट्स 28 मिनट बाद सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हो गए। इन सभी सैटलाइट्स को पीएसएलवी-सी37 की मदद से छोड़ा गया, यह इस रॉकेट का 39वां मिशन रहा। इस मिशन के तहत जिस प्रमुख भारतीय सैटलाइट्स को लॉन्च किया गया, वह कॉर्टोसैट-2 सीरीज का है।

ISRO की 5 बड़ी उपलब्धियां:

1. इसरो ने 15 फरवरी, 2017 को एक बार में एक साथ 104 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजकर रूस और अमेरिका के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इससे पहले रूस ने एक बार में एक साथ 37 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा था। वहीं, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अब तक एक बार में एक साथ 29 सैटेलाइट ही भेज पाया है। हालांकि आज से पहले इसरो ने एक बार में एक साथ 20 सैटेलाइट अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक भेजा था।
2. मंगलयान का कारनामा, दुनिया में ऐसा पहली बार- 5 नवंबर 2013 को इसरो ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पीएसएलवी सी 25 से मंगलयान को सफलतापूर्वक छोड़ा था, जो 24 सितंबर 2014 को मंगल पर पहुंचने में सफल हो गया। इस उपलब्धि के साथ ही भारत पहले ही प्रयास में मंगल पर यान भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। सोवियत रूस, अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद मंगल पर यान भेजने वाले देशों की कतार में भारत भी आ गया।
3. जीएसएलवी मार्क 3 का सफल प्रक्षेपण, इंसान को स्पेस में भेजने की उम्मीद- मंगलयान के बाद देश के सबसे बड़े रॉकेट जिओ सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क3 (जीएसएलवी) का सफल प्रक्षेपण दिसंबर 2014 में हुआ। इसकी सफलता से भारत अंतरिक्ष में इंसान भेज सकेगा, हालांकि इसमें अभी और समय लगेगा। अंतरिक्ष में इंसान भेजने की काबिलियत फिलहाल सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन के पास ही है।
4. जीएसएलवी मार्क 2 से उपग्रह प्रक्षेपण में आत्मनिर्भरता- जीएसएलवी मार्क 2 के सफल प्रक्षेपण से इसरो को बहुत बड़ी उपलब्धि मिली। इसमें भारत में ही बने क्रायोजेनिक इंजन को लगया गया था। इससे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए इसरो पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर हो गया।
5. दोबारा प्रयोग में आने वाला प्रक्षेपण यान आरएलवी का प्रक्षेपण- इसरो ने 2016 में तकनीकी तौर पर काफी विकास किया। इसने अपना नाविक सैटेलाइट नेविगेशन प्रणाली स्थापित करने के साथ ही दोबारा प्रयोग में आने वाले प्रक्षेपण यान आरएलवी और स्क्रैमजेट इंजन का सफल प्रयोग किया।

क्या है?

1. मंगलयान की कामयाबी के बाद इसरो की कमर्शल इकाई 'अंतरिक्ष' को लगातार विदेशी सैटलाइट्स लॉन्च करने के ऑर्डर मिल रहे हैं। इसरो पिछले साल जून में एक साथ 20 सैटलाइट्स लॉन्च कर चुका है।
2. इससे पहले तक इसरो 50 विदेशी सैटलाइट्स लॉन्च कर चुका था। पीएसएलवी-सी37 से पहले 714 किलोग्राम वजन के कॉर्टोसैट-2 सीरीज के सैटलाइट को पृथ्वी पर निगरानी के लिए प्रक्षेपित किया गया।
3. इसके बाद बाकी 103 सैटलाइट्स को पृथ्वी से करीब 520 किलोमीटर दूर पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में एक-एक कर प्रविष्ट कराया गया।

सैटेलाइट से जुड़ी बातें:

1. मिशन में मुख्य उपग्रह 714 किलोग्राम वजन वाला काटोसैट-2 सीरीज उपग्रह है जो इसी सीरीज के पहले प्रक्षेपित अन्य उपग्रहों के समान है।
2. इसके अलावा इसरो के दो तथा 101 विदेशी अति सूक्ष्म (नैनो) उपग्रहों का भी प्रक्षेपण किया जाना है, जिनका कुल वजन 664 किलोग्राम है।
3. विदेशी उपग्रहों में 96 अमेरिका के तथा इजरायल, कजाखस्तान, नीदरलैंड, स्विटजरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात के एक-एक उपग्रह शामिल हैं।
4. इसरो के इस मिशन में सैन फ्रांसिस्को की एक कंपनी के 88 छोटे सैटेलाइट लॉन्च किए गए।
5. भारत द्वारा ही विकसित ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान इसरो का सबसे विश्वस्त रॉकेट है। पीएसएलवी-सी 37 इस श्रेणी के रॉकेट का 39वां मिशन होगा।
6. अब तक पीएसएलवी की मदद से 38 मिशन को अंजाम दिया जा चुका है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

7. कार्टोसेट-2 सीरीज का उपग्रह धरती की निगरानी के इस्तेमाल में आएगा। इसके अलावा दो नैनो उपग्रह आईएनएस-1ए और आईएनएस-1बी को भी कक्षा में स्थापित किया।
8. इसरो ने इस मिशन में सबसे भारी PSLV का इस्तेमाल किया है। PSLV-37 का वजन 320 टन, ऊंचाई 44.4 मीटर।
9. 88 छोटे सैटेलाइटों का इस्तेमाल धरती की तस्वीरों के लिए किया जाएगा।
10. इसरो का यह रॉकेट 15 मंजिला इमारत जितना ऊंचा है।

वायुसेना में शामिल होगा AEW&C सिस्टम

भारत की आसमानी सीमा के अंदर अगर दुश्मन के लड़ाकू विमान, मिसाइल और ड्रोन घुसने की कोशिश करेंगे तो भारत अपनी 'आंख' से उसकी मौजूदगी भांप लेगा। इस काम में उसकी मदद करेंगे एयरबोर्न अर्ली वॉर्निंग एंड कंट्रोल (AEW&C) सिस्टम वाले विमान। इस सिस्टम से लैस विमानों को प्रतिष्ठित एरो इंडिया शो के दौरान वायुसेना में शामिल कर लिया जाएगा। इसमें कई ऐसे उपकरण लगाए गए हैं, जो देश में ही विकसित किए गए हैं।

क्या है?

1. एरो इंडिया शो 14 से 18 फरवरी के बीच बेंगलुरु में होगा। डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (डीआरडीओ) ने AEW&C सिस्टम वाले विमान को 14 फरवरी को वायुसेना में शामिल होने के लिए भेजे जाने की पुष्टि की है।
2. एनबीटी ने पहले को ही इस बारे में जानकारी दे दी थी। रिपब्लिक डे परेड के दौरान पहली बार इस सिस्टम से युक्त विमान को पब्लिक के बीच लाया गया था।
3. अपना AEW&C सिस्टम हासिल करते ही भारत इस मामले में टॉप पांच देशों में शामिल हो जाएगा। भारत ने इस सिस्टम के लिए 2008 में ही ब्राजील से विमान खरीदे थे। कुछ कारणों से 2200 करोड़ रुपये का यह प्रॉजेक्ट लेट होता चला गया।
4. दुश्मन के विमान पर नजर रखने के लिए AWACS (एयरबोर्न वॉर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम) नाम के एक और प्रोग्राम पर काम चल रहा है।
5. AEW&C सिस्टम में 240 डिग्री कवरेज वाला रेडार है, जबकि AWACS से 400 किलोमीटर तक 360 डिग्री कवरेज हासिल हो सकेगी। करीब 5100 करोड़ रुपये के इस प्रॉजेक्ट के तहत आठ विमानों को शामिल करने की योजना है। यह सिस्टम 2024 तक ही उपलब्ध हो पाएगा।
6. फिलहाल इस काम के लिए भारत के पास फाल्कन सिस्टम है, जिसमें रूसी विमान पर इस्रायली रेडार लगे हैं। यह 400 किलोमीटर तक 360 डिग्री कवरेज देने में सक्षम है।
7. इस मामले में भारत फिलहाल चीन और पाकिस्तान से काफी पीछे माना जाता है। चीन के पास 20 से ज्यादा सिस्टम हैं, जबकि पाकिस्तान के पास आठ सिस्टम बताए जाते हैं।
8. चीन का सिस्टम 470 किलोमीटर की दूरी तक 60 से ज्यादा विमानों को ट्रैक कर सकता है। पाकिस्तान के पास चार स्वीडिश और चार चीनी विमान हैं।

रक्षा क्षेत्र में भारत की एक और उड़ानः

भारत ने ओडिशा के तट से अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रायोगिक परीक्षण किया और द्विस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने की दिशा में एक अहम उपलब्धि हासिल की।

क्या है?

1. इस इंटरसेप्टर को आईटीआर के अब्दुल कलाम द्वीप 'व्हीलर द्वीप' से प्रक्षेपित किया गया। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के एक अधिकारी ने कहा कि पीडीवी नामक यह अभियान पथ्वी के वायुमंडल से 50 किमी उपर बाहरी वायुमंडल में स्थित लक्ष्यों के लिए है।
2. पीडीवी इंटरसेप्टर और दो चरणों वाली लक्ष्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ। लक्ष्य को दरअसल 2000 किमी से अधिक दूरी से आती शत्रु बैलिस्टिक मिसाइल के तौर पर विकसित किया। इसे बंगाल की खाड़ी में एक पोत से दागा गया।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

3. एक स्वचालित अभियान के तहत रडार आधारित प्रणाली ने शत्रु की बैलिस्टिक मिसाइल की पहचान कर ली। रडार से मिले आंकड़ों की मदद से कंप्यूटर नेटवर्क ने आ रही बैलिस्टिक मिसाइल का मार्ग पता लगा लिया।
4. पीडीवी को पूरी तरह तैयार रखा गया था। कंप्यूटर सिस्टम से जरूरी निर्देश मिलते ही इसे छोड़ दिया गया। यह अहम दिशासूचक प्रणालियों की मदद से अवरोधन बिंदू तक पहुंच गई।
5. सभी कार्यों का निरीक्षण विभिन्न स्थानों पर स्थित टेलीमीट्री रेंज स्टेशनों ने तत्काल आधार पर किया।

चिकित्सा उपकरण नियम 2017 अधिसूचितः

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 अधिसूचित कर दिए हैं। नए नियम ग्लोबल हार्मोनाइजेशन टॉस्के फोर्स (जीएचटीएफ) फ्रेमवर्क के अनुरूप बनाए गए हैं और सर्वोत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीरय पद्धतियों की पुष्टि करते हैं। नए नियमों का लक्ष्य भारत में निर्माण यानी मेक इन इंडिया के मार्ग की नियामक कठिनाइयों को दूर करते हैं, व्यापार में सुगमता लाने में सहायक हैं और बेहतर रोगी देखभाल एवं सुरक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हैं।

क्या है?

1. नए नियमों के अंतर्गत चिकित्सा उपकरण विनिर्माताओं को जोखिम अनुपात नियामक अपेक्षाएं पूरी करनी होंगी, जिनका उल्लेख नियमों में किया गया है और जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के अनुरूप हैं।
2. चिकित्सा उपकरणों में नियमन में सर्वोच्च व्यावसायिकता लाने के लिए अधिसूचित निकायों के जरिए तृतीय पक्ष समरूपता मूल्यांकन और प्रमाणन की व्यमवस्था की गई है।
3. नियमों में चिकित्सा उपकरण विनिर्माताओं द्वारा आत्मा-अनुशासन की संस्कृति विकसित करने की अपेक्षा की गई है और तदनुरूप श्रेणी ए के चिकित्सान उपकरणों के लिए विर्माण लाइसेंस विनिर्माण स्थल की पूर्व जांच किए बिना ही मंजूर कर दिए जायेंगे। ऐसे मामलों में विनिर्माता को अपेक्षाएं पूरी करने के बारे में स्वायं प्रमाणपत्र देना होगा। परन्तु बी और सी श्रेणी के चिकित्सा उपकरणों के मामले में अधिसूचित निकायों द्वारा पूर्व जांच अनिवार्य होगी।
4. नए नियमों में कई अन्य विशिष्टताएं हैं। यह पहला अवसर है कि लाइसेंस का समय-समय पर नवीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी। तदनुरूप विनिर्माण या आयात लाइसेंस तब तक वैध समझे जाएंगे, जब तक कि उन्हें निलंबित या रद्द नहीं कर दिया जाता।

नया कालाजार प्रोग्राम शुरूः

विभिन्न बीमारियों से लड़ने को ले कर सरकार के संकल्प की बजट में घोषणा के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कालाजार निर्मूलन के लिए 'एक्सेलरेटेड कालाजार एलिमिनेशन प्रोग्राम' शुरू कर दिया है। सरकार को उम्मीद है कि इसकी मदद से नवंबर तक कालाजार निर्मूलन में कामयाबी मिल जाएगी।

क्या है?

1. इस बजट के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र के आवंटन में हुई 23 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी नई योजनाओं के लिए कमर कर ली है।
2. काला जार को समाप्त करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के साथ बैठक कर तय किया कि जिन 93 ब्लॉक में यह बीमारी अब तक बची हुई है, उस पर केंद्र और राज्य सरकार ही नहीं बल्कि सभी डेवलपमेंट पार्टनर भी पूरी तरह जुट कर इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। ताकि दिसंबर तक इसका निर्मूलन किया जा सके। मंत्रालय के अधिकारी कहते हैं कि छह महीने पहले तक 153 ब्लॉक इससे प्रभावित थे, लेकिन अब इसे 93 तक पहुंचा दिया गया है। इनमें से 75 फीसदी प्रभावित ब्लॉक बिहार में हैं। हालांकि निर्मूलन का प्रमाणपत्र तीन साल के बाद ही मिलता है।

एमआर टीकाकरण अभियान का शुभारंभः

स्वास्थ्य और परिवार कल्यानण मंत्रालय ने बेंगलूरू में आयोजित एक समारोह में देश में मीजल्स रूबेल (एमआर) टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इन दो बीमारियों के खिलाफ अभियान पांच राज्योंर/संघशासित प्रदेशों (कर्नाटक, तमिलनाडू, पुदुच्चेरी, गोवा और लक्षद्वीप) से शुरू किया जायेगा, जिसके अंतर्गत करीब 3.6 करोड़ बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। इस अभियान के बाद मीजल्से रूबेल (एमआर) टीका नियमित रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा, जो वर्तमान में दी

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

जा रही मीजल्सर की खुराक का स्थागन लेगा। वर्तमान में यह खुराक दो बार यानी 9-12 महीने और 16-24 महीने की आयु के बच्चों को दी जाती है।

क्या है?

1. टीके के उद्घाटन के अवसर पर केन्द्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री श्री सदानंद गौडा, केन्द्री य संसदीय कार्य, रसायन और उर्वरक मंत्री श्री अनन्तय कुमार, केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री फग्गसन सिंह कुलस्ते, कर्नाटक सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डा. शरणप्रकाश रूद्राप्पाय पाटिल, कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य राज्यजमंत्री श्री के आर रमेश और जाने-माने अभिनेता श्री रमेश अरविन्दर उपस्थित थे। गणमान्यट व्यक्तियों ने इस अवसर पर अभियान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संचार सामग्री का विमोचन भी किया।
2. इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्री फग्न सिंह कुलस्तेर ने कहा कि सरकार देश को चेचक (मीजल्स) और हलका खसरा (रूबेल) से मुक्तर करने के प्रति वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस काम में राज्य सरकारों, गैर सरकारी संगठनों और विश्व् स्वास्थ्य संगठन, यूनिसेफ, गेट्स फाउंडेशन, लायन्स क्लब, आईपीए, आईएमए आदि विकास भागीदारों को शामिल करेगी।
3. एमआर अभियान का लक्ष्य देशभर में करीब 41 करोड़ बच्चों को लाभ पहुंचाना है। इन सभी की आयु 9 महीने से 15 वर्ष के बीच है।

देश के सबसे बड़े स्कूल खेल पंहुच कार्यक्रम का शुभारम्भः

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की फुटबॉल को देश का पसंदीदा खेल बनाने की परिकल्पआना से प्रेरित सबसे बड़े स्कूल खेल पंहुच कार्यक्रम, मिशन इलेवन मिलियन का युवा मामले और खेल राज्यमंत्री (स्वपतंत्र प्रभार) श्री विजय गोयल ने शुभारम्भ किया। इस अवसर पर एआईएफएफ के अध्यक्ष श्री प्रफुल्ल पटेल भी उपस्थित थे। अपनी तरह के इस पहले कार्यक्रम से बच्चों को खूबसूरत खेल फुटबॉल खेलने का बढ़ावा मिलेगा, उनकी स्वस्थ आदतें बनेंगी और वे एक साथ काम करने तथा खेल भावना का जीवन का महत्वपूर्ण सबक सीखेंगे। इसके जरिए स्कूल के प्रधानाचार्यों और खेल शिक्षकों को बच्चों को नियमित फुटबॉल खेलने को बढ़ावा देने तथा जागरूक करने के लिए कहा जाएगा।

क्या है?

1. पिछले साल अक्टूबर में फीफा अंडर 17 विश्व कप का भारत में आयोजन कर हम अपने बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहे हैं तथा वैश्विक खेल कार्यक्रम आयोजित करने में हमारी क्षमताओं का प्रदर्शन कर रहे हैं।
2. 27 मार्च के अपने 'मन की बात' रेडियो कार्यक्रम में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने फीफा अंडर 17 विश्व कप 2017 को युवाओं के लिए बड़ा अवसर बताते हुए कहा था कि इससे देशभर में खेल क्रांति शुरू हो सकती है। उनके शब्दों में इस पूरे साल में स्कूलों और कॉलेजों तथा देशभर में फुटबॉल का वातावरण रहना चाहिए।
3. यह फुटबॉल के लिए स्कूलों को शामिल करने का विशाल कार्यक्रम है। अंतर्राष्ट्रीय खेल विशेषज्ञताओं लेकिन हमारे विशाल और विविध देश की जमीनी हकीकतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के प्रत्येक इलाके के 11 मिलियन बच्चों में फुटबॉल के प्रति जुनून पैदा करना है।
4. मिशन इलेवन मिलियन का महत्वपूर्ण विचार है कि प्रत्येक बच्चे को विश्वों के सबसे लोकप्रिय खेल को खेलने का अवसर मिलना चाहिए। इसे सफल बनाने के लिए स्कूलों और माता-पिता को भी बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि मिशन इलेवन मिलियन के जरिए बच्चों को नियमित खेल खेलने के लिए प्रोत्सांहित करने के लिए माता-पिता और स्कूलों को उपकरण और ज्ञान प्रदान किया जाता है।
5. यह कार्यक्रम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर इम्फाल तक देश के सभी राज्यों में शुरू किया जाएगा। शुरूआती कार्य पहले ही आरंभ हो गए हैं और स्कूलों तथा बच्चों से मिली प्रतिक्रिया से सरकार बहुत उत्सारहित है।
6. मिशन इलेवन मिलियन खुबसूरत खेल फुटबॉल को देश के कम से कम 11 मिलियन लड़कों और लड़कियों तक ले जाएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ से अरूणाचल प्रदेश तक प्रत्येक राज्य में बच्चों को फुटबॉल सीखने, खेलने और इसका मजा लेने का अवसर मिलेगा।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

राष्ट्रगान पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश:

फिल्म के दौरान राष्ट्रगान पर सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित आदेश जारी किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि फिल्म के दौरान राष्ट्रगान बजने पर खड़े होने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि अभी इस मामले को लेकर देश में कोई कानून नहीं है। इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नैतिकता के पहरेदार नहीं हैं, मुद्दे पर बहस हो। हालांकि फिल्म से पहले बजने वाले राष्ट्रगान पर खड़ा होना अनिवार्य है। गौरतलब है कि इससे पहले दिसंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमाघरों में राष्ट्रगान बजने से पहले सभी दर्शकों को सम्मान में खड़ा होने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि राष्ट्रीय गान बजते समय सिनेमाहॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा। श्याम नारायण चौकसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि सिनेमा हॉल में प्रत्येक फिल्म के प्रदर्शन से पहले हर बार राष्ट्र गान बजाया जाए।

क्या है पूरा मामला?

1. 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि सभी सिनेमा घरों में फिल्म के शुरू होने से पहले राष्ट्रगान चलवाना होगा। इसके अलावा राष्ट्रगान के वक्त स्क्रीन पर तिरंगा भी दिखाना जरूरी किया गया था।
2. राष्ट्रगान के सम्मान में सभी दर्शकों को खड़ा होना होगा यह भी कहा गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें राष्ट्रगान के दौरान खड़े ना होने वाले की पिटाई की गई।
3. राष्ट्रगान बजाने की जनहित याचिका श्याम नारायण चौकसे नाम के शख्स ने डाली थी।
4. उन्होंने मांग की थी कि देशभर में सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए और इसे बजाने तथा सरकारी समारोहों और कार्यक्रमों में इसे गाने के संबंध में उचित नियम और प्रोटोकॉल तय होने चाहिए जहां संवैधानिक पदों पर बैठे लोग मौजूद होते हैं।

बहुमुखी हेलीकॉप्टर के मॉडल का अनावरण:

पांच दिनों तक चलने वाले एयरो इंडिया-2017 एयर शो का यहां शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर ने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) के भारतीय बहुमुखी हेलीकॉप्टर (आइएमआरएच) के मॉडल का अनावरण किया। एचएएल का लक्ष्य स्वदेश में 12 टन के आइएमआरएच विकसित करने का है। 24 सीटों वाला यह हेलीकॉप्टर करीब 20,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकेगा और 3,500 किलो भार वहन करने में सक्षम होगा। हेलीकॉप्टर सैन्य ट्रांसपोर्ट, घायलों को निकालने, लड़ाई के दौरान खोज एवं बचाव अभियान, वीआइपी/वीवीआइपी लोगों को लाने-ले जाने और एयर एंबुलेंस के काम में उपयोगी हो सकता है। प्रस्तावित आइएमआरएच दो इंजनों और ऑटोमैटिक फ्लाइट कंट्रोल प्रणाली से लैस होगा। अनावरण के दौरान गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर और एचएएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक टी. सुवर्ण राजू भी मौजूद थे।

कामोव समझौते को अंतिम रूप:

1. रक्षा क्षेत्र की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एयरोनॉक्सि लिमिटेड और रूसी रक्षा कंपनी रोसोबोरोनएक्सपोर्ट ने कामोव 226टी हेलीकॉप्टर के निर्माण को लेकर संयुक्त उपक्रम के समझौते को अंतिम रूप दिया है। इस हल्के और बहुमुखी हेलीकॉप्टर का भारत में निर्माण होना है।
2. अब दोनों देशों के संबंधित विभागों से दस्तावेज को औपचारिक मंजूरी का इंतजार है। रूसी कंपनी के अधिकारी के मुताबिक, इसमें एक-दो महीने और लग सकते हैं। दिसंबर 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान दोनों देशों की सरकारों ने इस संबंध में समझौते पर हस्ताक्षर किए थे।

क्या है?

1. इसके अलावा एयर शो के दौरान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) निर्मित एमबीटी अर्जुन एमके 2 के नए हथियार नियंत्रण प्रणाली का भी अनावरण किया गया। रिमोट कंट्रोल्ड स्टेशन (आरसीडब्ल्यूएस)/एयर डिफेंस वेपन स्टेशन (एडीडब्ल्यूएस) हाथ से संचालित एयर डिफेंस गन का उन्नत संस्करण है।
2. इससे सैनिक युद्धक टैंक के अंदर सुरक्षित रहकर हवा में गोले दाग सकता है।
3. एमबीटी एमके 2 टैंक को आरसीडब्ल्यूएस से लैस करने का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं में रिमोट फायरिंग विकल्प, दिन का कैमरा एवं नाइट विजन, ऑटोमैटिक टारगेट ट्रैकिंग आदि शामिल हैं।

ब्रह्मोस की रेंज होगी 450 किमी:

भारत अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की रेंज 290 किलोमीटर से बढ़ाकर 450 किलोमीटर करने जा रहा है। इस संबंध में एक परीक्षण अगले महीने 10 मार्च को होगा। डीआरडीओ के प्रमुख एस. क्रिस्टोफर ने बताया कि ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 450 किमी करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बदलने की जरूरत होगी। इसे परखने के लिए इसका परीक्षण अगली दस तारीख को होगा।

क्या है?

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

1. इसके अलावा, डीआरडीओ ब्रह्मोस मिसाइल का दूसरा वर्जन भी विकसित करने की तैयारी कर रहा है। 800 किमी रेंज वाले ब्रह्मोस मिसाइल की इस श्रृंखला को विकसित करने में और ढाई साल लगेंगे।
2. ब्रह्मोस भारतीय सेना में वर्ष 2007 से तैनात है। ब्रह्मोस की तीन श्रृंखलाएं सेना का हिस्सा हैं और यह सभी ब्लाक-3 वर्जन से लैस हैं।
3. ब्रह्मोस को जमीन, समुद्र, समुद्र के अंदर और हवा से लांच किया जा सकता है।
4. लेकिन उन्होंने अग्नि-5 मिसाइल की रेंज बढ़ाने की योजना से इन्कार कर दिया। अग्नि मिसाइल का रेंज फिलहाल 5000 किलोमीटर से अधिक है, जोकि बीजिंग तक को निशाना बना सकती है।
5. भारत जून 2016 में ही मिसाइल टेक्नोलाजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर) का सदस्य बना है। एमटीसीआर मिसाइल का प्रसार रोकने और 300 किमी के दायरे में 500 किग्रा भार का पेलोड ले जाने वाले मानवरहित एरियल वेहिकल टेक्नोलाजी को नियंत्रित करने की अनौपचारिक और ऐच्छिक साझेदारी करता है।
6. इससे सदस्य देशों को इस संगठन के बाहर किसी अन्य देश को तकनीक देने से रोका जाता है।

मार्च में दक्षेस उपग्रह लांच करने की योजना:

एक साथ 104 उपग्रहों को लांच करने का रिकॉर्ड बनाने के बाद इसरो की मार्च और अप्रैल में दो उपग्रहों के प्रक्षेपण की योजना है। इनमें से एक उपग्रह दक्षेस देशों के लिए होगा। इसरो के अध्यक्ष एएस किरण कुमार ने बताया कि दोनों उपग्रहों को लांच करने की तैयारियां जोरों पर हैं। जीएसएलवी मार्क-2 दक्षेस उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाएगा। जबकि जीएसएलवी मार्क-3 संचार उपग्रह जीसेट-19 को ले जाएगा।

क्या है?

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवंबर 2014 में नेपाल में दक्षेस सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों को उपहारस्वरूप दक्षेस उपग्रह लांच करने की घोषणा की थी। इससे इन देशों को टेलीकॉम और टेलीमेडिसिन समेत विभिन्न क्षेत्रों में लाभ मिलेगा।
2. परियोजना से पाकिस्तान के हटने के बाद दक्षेस उपग्रह को अब दक्षिण एशियाई उपग्रह कहा जाएगा। चंद्रयान-2 के लांच के बारे में पूछे जाने पर इसरो प्रमुख ने कहा कि इसके लिए हमारा लक्ष्य 2018 की शुरुआत का है। मानव सहित अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के बारे में उन्होंने कहा कि अभी यह हमारी प्राथमिकता नहीं है।
3. अमेरिकी कंपनियां अपने नैनो उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो को तरजीह देती हैं। उन्होंने कहा कि इसरो अंतरिक्ष अभियान के खर्च को कम करने के लिए अन्य उपाय तलाश रहा है।

कर्नाटक में कंबाला विधेयक पारित:

कर्नाटक में परंपरागत भैंसा दौड़ 'कंबाला' और बैलदौड़ व भैंसागाड़ी दौड़ (Kambala, and Bulls race or Bullock cart race) को कानूनी मान्यता प्रदान करने वाला विधेयक सभी दलों के समर्थन के साथ 13 फरवरी को राज्य विधानसभा में पारित हो गयाद्य मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विधेयक के पास होने के बाद इस खेल को कानूनी मान्यता मिल जाएगी।

क्या है?

1. तमिलनाडु सरकार की ओर से सांडों के खेल जल्लीकट्टू को कानूनी रूप देने के लिये विधेयक लाने के बाद अब

पृष्ठभूमि

1. भैंसा गाड़ी दौड़ों का आयोजन प्रमुख रूप से शिवमोग्गा और उत्तरी कर्नाटक के भागों में तथा 'कंबाला' का उडुपी और दक्षिण कन्नड़ में किया जाता है।
2. इस खेल का मार्ग प्रशस्त करने के लिये 28 जनवरी को राज्य मंत्रिमंडल ने पशुओं के क्रूरता निवारण अधिनियम (1960 का केन्द्रीय अधिनियम) को संशोधित करने का निर्णय लिया गया था।
3. ध्यातव्य है कि इस अधिनियम को पशुओं पर होने वाली अनावश्यक क्रूरता और कष्टों को रोकने के लिये सजा देने हेतु लागू किया गया था।
4. मुख्य न्यायाधीश एस.के. मुखर्जी की अध्यक्षता में कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पिछले वर्ष नवम्बर माह में "पेटा" की याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जल्लीकट्टू के संदर्भ में दिये गए निर्देशों का हवाला देते हुए इसे चुनौती दी थी।
5. हाल ही में, 30 जनवरी को उच्च न्यायालय ने कहा था कि वह जल्लीकट्टू के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करेगा।
6. इससे पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा था कि उनकी सरकार इस आयोजन की समर्थक है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में भी उसी तरह का अनुकूल कदम उठाना चाहिये जैसा कि उसने जलीकट्टू के मामले में उठाया है। इस मसले पर हम विचार करेंगे और जरूरी हुआ तो अध्यादेश भी ला सकते हैं।
7. जल्लीकट्टू आंदोलन से प्रेरित होकर मंगलुरु की कम्बाला समितियों ने बैठक करके तय किया था कि दक्षिण कन्नड़ जिले के मूडबिडरी में विशाल प्रदर्शन किया जाएगा।
8. विदित हो कि पेटा ने पशुओं की क्रूरता के संदर्भ में कंबाला का विरोध किया था।
9. नवम्बर से मार्च तक होने वाले कंबाला में हल के साथ भैंसों के जोड़े को बाँधा जाता है तथा इसे एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है, उन्हें कीचड के समानांतर पथों पर दौड़ाया जाता है तथा इसमें सबसे तेज भागने वाली टीम विजयी होती है।
10. यह विश्वास किया जाता है किसानों के लिये मनोरंजक खेल होने के अतिरिक्त इसका आयोजन अच्छी पैदावार होने के लिये ईश्वर को प्रसन्न करने के उद्देश्य से किया जाता है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

कर्नाटक में भैसों की पारंपरिक दौड़ 'कंबाला' संबंधित विधेयक को कर्नाटक विधानसभा में सर्वसम्मति से पास कर दिया गया है।

2. कंबाला एक परंपरागत लोक खेल है तथा इसमें जानवरों के प्रति क्रूरता का भाव नहीं है। जनमानस की यह एक प्रमुख इच्छा है कि इसे भी अनुमति प्रदान की जाए।
3. विधेयक के सन्दर्भ में पशुपालन मंत्री ए.मंजू ने कहा है कि कानून मंत्री टी.बी. जयचन्द्र की अध्यक्षता में गठित एक समिति द्वारा यह प्रस्तावित किया गया कि कंबाला को एक बैलगाड़ी दौड़ के समान ही अनुमति प्रदान की जानी चाहिये क्योंकि इसमें पशुओं के लिये क्रूरता का कोई भाव नहीं है तथा यह कृषि व किसानों के विश्वास से संबंधित है।
4. पशुपालन मंत्रालय के अनुसार हालाँकि, सरकार चाहती तो तमिलनाडु की तरह अध्यादेश ला सकती थी किन्तु उसने अध्यादेश के स्थान पर लोकतांत्रिक तरीके से कानून में संशोधन लाकर, इस विधेयक को वैधता प्रदान करने को वरीयता दी है।
5. इस विधेयक में यह भी संकेत किया गया है कि 'कंबाला' और बैलों की दौड़ अथवा बैलगाड़ी दौड़ इत्यादि परम्परागत खेलों द्वारा राज्य की परम्पराओं को संरक्षित करने, उन्हें बढ़ावा देने और सांस्कृतिक आदान-प्रदान में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। साथ ही, इन खेलों की मवेशियों की इन खास नस्लों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका भी है।

अंतर्राष्ट्रीय

10 परमाणु हथियार एक साथ ले जाने वाली मिसाइल का परीक्षण:

बढ़ रही चुनौतियों के बीच चीन ने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जिससे दस परमाणु बम ले जाकर अलग-अलग स्थानों पर डाले जा सकते हैं। परीक्षण में डीएफ-5 सी नाम की इस मिसाइल को नकली बम लगाकर शांक्शी प्रांत में स्थित ताइयुआन स्पेस लांच सेंटर से छोड़ा गया। मिसाइल ने पश्चिमी चीन के रेगिस्तान में जाकर लक्ष्यों पर सही मार की।

क्या है?

1. नई मिसाइल करीब तीन दशक पहले परीक्षण की गई चीन की अंतर महाद्वीपीय मिसाइल (आइसीबीएम) डीएफ-5 का उन्नत संस्करण है। वाशिंगटन फ्री बीकन नाम की अमेरिकी पत्रिका ने इस परीक्षण की जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिका के खुफिया तंत्र को इस परीक्षण की जानकारी है।
2. माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव बढ़ने की आशंका से चीन ने यह परीक्षण किया है।
3. दशकों से कायम अमेरिकी मान्यता के अनुसार चीन के पास 250 परमाणु बम हैं। लेकिन दस बमों वाली मिसाइल का परीक्षण करने से माना जा रहा है कि चीन के भंडार में 250 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं।
4. अमेरिकी रक्षा मंत्रालय के अधिकारी लंबी दूरी की मिसाइलों के परीक्षण को लेकर पहले ही चेतावनी जारी कर चुके हैं। अब उसके पास परमाणु हथियारों की संख्या को लेकर भी शंका पैदा हो गई है। इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरनाक माना जा रहा है। लेकिन चीनी रक्षा विशेषज्ञ इसे चीन की सामान्य रक्षा प्रक्रिया के तौर पर देख रहे हैं।

रेक्स टिलर्सन ने अमेरिकी विदेश मंत्री पद की शपथ ली:

रेक्स टिलरसन को अमेरिका के विदेश मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनके करीबी रिश्ते को लेकर जताई जा रही चिंता के बावजूद सीनेट ने उनकी नियुक्ति की पुष्टि कर दी थी।

क्या है?

1. 64 वर्षीय टिलरसन एक्सन मोबिल के चेयरमैन एवं मुख्य कार्यकारी रह चुके हैं। सीनेट ने 56 के मुकाबले 43 मतों से उनकी नियुक्ति की पुष्टि की है।
2. अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने उन्हें शपथ दिलाई। इससे पहले टिलरसन राजनीतिक पद पर नहीं रहे हैं।
3. ह्वाइट हाउस के ओवल आफिस में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, श्मध्य पूर्व और पूरी दुनिया में ढेर सारी चुनौतियों के बावजूद मुझे शांति और स्थायित्व का लक्ष्य हासिल कर लेने का भरोसा है।श

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

4. सीनेट की न्यायिक समिति ने अमेरिका के अटार्नी जनरल पद पर जेफ सेसन्स के नामंकन को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अटार्नी जनरल सैली याटेस को हटाने से डेमोक्रेटिक पार्टी नाराज है। विरोध के कारण मंजूरी मिलने में देरी हुई।

संयुक्त राष्ट्र ने गुलबुद्दीन हेक्मतयार को आतंकी सूची से हटाया:

संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री एंव चरमपंथी नेता गुलबुद्दीन हेक्मतयार का नाम आतंकवादियों की सूची से हटा दिया है जिसके बाद पूर्व में भारत विरोधी रुख रखने वाले इस चरमपंथी नेता की जब्त की गई संपत्ति और यात्रा पर लगी रोक तथा हथियार रखने पर लगा प्रतिबंध समाप्त हो गया है। इन्होंने अफगानिस्तान सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह नेता काबुल के कसाई के नाम से भी जाना जाता है।

क्या है?

1. सुरक्षा परिषद् की अलकायदा प्रतिबंध समिति ने हेक्मतयार का नाम आईएसआईएस और अलकायदा प्रतिबंधित सूची से कल हटा दिया।
2. प्रतिबंध समिति ने एक बयान जारी करके कहा कि इसलिए संपत्ति पर रोक, यात्रा प्रतिबंध और हथियार रखने का प्रतिबंध अब हेक्मतयार पर लागू नहीं होगा। बयान में 67 वर्षीय इस चरमपंथी नेता के बारे में विस्तृत जानकारी देने हुए कहा गया कि इसका नाम 20 फरवरी 2003 को सूची में डाला गया था और माना जाता था कि साल 2011 तक वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में था।
3. हिज्ब-ए-इस्लामी आतंकी समूह के प्रमुख हेक्मतयार ने पिछले साल सितंबर में अफगानिस्तान सरकार के साथ एक एतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया था और नेता के कुछ सप्ताह में देश वापस लौटने की संभावना है। इस समझौते ने उसके लिए देश वापसी और संभवत: राजनीतिक जीवन में आने का भी रास्ता तैयार कर दिया है।
4. साल 1997 से छिप कर रहने वाले इस नेता के बारे में बड़े पैमाने पर माना जाता है कि वह पाकिस्तान में हैं। चरमपंथी नेता के बारे में विश्वास है कि इसका घनिष्ठ संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ है और वह भारत विरोधी रुख रखता है।
5. पूर्व प्रधानमंत्री हेक्मतयार सोवियत विरोधी कमांडर था और साल 1992-1996 तक चले गृह युद्ध में हजारों लोगों को मारने का आरोपी है।

भारत-ब्रिटेन संस्कृति वर्ष लांचिंग की मेजबानी करेंगी एलिजाबेथ:

महारानी एलिजाबेथ द्वितीय बकिंघम पैलेस में ब्रिटिश-भारत संस्कृति वर्ष की लांचिंग की मेजबानी करेंगी। यह समारोह 27 फरवरी को आयोजित किया जाएगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक साझीदारी को मजबूती देना है।

क्या है?

1. भारतीय मूल की मंत्री प्रीती पटेल ने कार्यक्रम को दोनों देशों के संबंध का वास्तविक प्रदर्शन बताया है। इस कार्यक्रम में पटेल सहित ब्रिटेन के प्रमुख कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। अंतरराष्ट्रीय विकास के लिए ब्रिटेन की विदेश मंत्री पटेल ने कहा, 'यह भव्य कार्यक्रम भारत-ब्रिटेन संबंध का उत्सव मनाने का बेहतरीन अवसर होगा।'
2. इस सप्ताह के शुरू में ही पैलेस ने 27 फरवरी को समारोह आयोजित किए जाने की अधिकृत घोषणा कर दी थी। शाही कार्यक्रम कैलेंडर के तहत की गई घोषणा के मुताबिक, महारानी, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग ब्रिटेन-भारत संस्कृति वर्ष 2017 की मेजबानी करेंगे।
3. 90 वर्षीया एलिजाबेथ द्वितीय दुनिया में लंबी अवधि तक शासन करने वाली महारानी मानी गई हैं। वह 65 वर्षो से ब्रिटेन की महारानी हैं। इस कार्यक्रम में भारत के वरिष्ठ कबीना मंत्री सहित दोनों देशों के विभिन्न क्षेत्रों के सैकड़ों अतिथि हिस्सा लेंगे।

चीनी सेना ने अत्याधुनिक मिसाइल के साथ किया अभ्यास:

चीन में हाल ही गठित रॉकेट फोर्स ने अत्याधुनिक DF-16 मीडियम रेंड बलिस्टिक मिसाइलों के साथ अभ्यास किया है। ये मिसाइलें करीब एक हजार किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। भारत के साथ साथ जापान और अमेरिका भी इसकी जद में आते हैं। आमतौर पर अपने हथियारों के बेड़े और सैन्य क्षमताओं को गुप्त रखने वाली चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) ने हाल ही में किए गए एक सैनिक अभ्यास का एक विडियो जारी किया है। इस विडियो में इन DF-16 मीडियम रेंड बलिस्टिक को दिखाया गया है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

क्या है?

1. इस फुटेज में कई लॉन्च वीइकल्स में ये मिसाइलें लदी हुई दिखाई दे रही हैं। बता दें कि चीन ने अपने मिसाइलों और इससे जुड़े सैन्य साजो-सामान के लिए अलग से एक रॉकेट फोर्स बनाई हुई है।
2. इस ड्रिल में भाग लेने वाले चीनी सैनिकों ने अलग-अलग युद्ध परिस्थितियों, मसलन-रसायनिक/बायलॉजिकल हमला, उपग्रह से जासूसी की कोशिशों का मुकाबला करने और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की स्थिति में क्या रणनीतियां अपनाई जानी चाहिए, इनका भी अभ्यास किया।
3. यह तीसरा मौका था जब इन मिसाइलों का सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया।
4. सितंबर 2015 में राजधानी पेइचिंग में आयोजित एक सैन्य परेड में पहली बार यह मिसाइल दिखा था। इसके बाद फिर जुलाई 2016 में एक टीवी न्यूज कार्यक्रम के दौरान सेंट्रल मिलिटरी कमिशन के उपाध्यक्ष को DF-16 यूनिट का निरीक्षण करते हुए दिखाया गया था।
5. इसमें यह मिसाइल भी नजर आया था। चीन की सरकार ने अपने बलिस्टिक मिसाइल्स का ब्योरा कभी सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि DF-16 फर्स्ट आइलैंड चेन में तैनात अन्य राष्ट्रों की सेनाओं के लिए एक गंभीर चुनौती है।
6. जापान से लेकर उत्तर में ताइवान और दक्षिण में फिलीपीन्स तक फैले द्वीपसमूह को चीन की सेना 'फर्स्ट आइलैंड चेन' के नाम से पुकारती है।
7. सैन्य मामलों के विशेषज्ञ एक अमेरिकी चौनल 'वॉशिंगटन फ्री बेकन' ने 31 जनवरी को खबर चलाई कि चीन ने अपने DF-5C अंतर्महाद्वीपीय बलिस्टिक मिसाइलों को पहली उड़ान जनवरी में उड़ाया।
8. चीन ने रूस के साथ सटी अपनी सीमा के पास एक लंबी दूरी के मिसाइल को भी तैनात किया है। रूस की मीडिया का कहना है कि इस मिसाइल का निशाना अमेरिका की ओर है। चीन की आधिकारिक मीडिया में छप रही खबरों के मुताबिक, चीन अमेरिका के साथ संभावित सैन्य संघर्ष की तैयारियां तेज कर रहा है।

अमेरिका और जापान ने किया संयुक्त मिसाइल परीक्षणः

उत्तर कोरिया के मिसाइल कार्यक्रम पर बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और जापान ने एक संयुक्त तंत्र का इस्तेमाल करते हुए पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल लक्ष्य अवरोधन का परीक्षण किया। अमेरिका और जापान वर्ष 2006 से ही स्टैंडर्ड मिसाइल-3 के एक स्वरूप को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं।

क्या है?

1. यह पोत से प्रक्षेपित की जाने वाली एक ऐसी मिसाइल है, जो एजिस बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा तंत्र के हिस्से के रूप में काम करती है।
2. अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी (एमडीए) ने कहा कि परीक्षण हवाई के काउई के तट पर हुआ। इसमें स्टैंडर्ड मिसाइल-3 'ब्लॉक 2ए' ने अंतरिक्ष में अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेद दिया। एमडीए के अनुसार, अब तक अमेरिका इस तंत्र पर 2.2 अरब डॉलर और जापान लगभग एक अरब डॉलर खर्च कर चुका है।

दक्षिण चीन सागर पर चीन ने US को दी सलाह

दक्षिण चीन सागर और वन चाइना पॉलिसी के मुद्दे पर चीन और अमेरिकी प्रशासन आमने-सामने हैं। अमेरिका ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि दक्षिण चीन सागर और चीन की विस्तारवादी नीति का वो विरोध करता रहेगा। लेकिन अमेरिका की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए चीन ने कहा कि यूएस में जो अधिकारी बैठे हुए हैं, उन्हें एक बार फिर इतिहास पढ़ने की जरूरत है। चीन के विदेश मंत्री वैंग यी ने कहा कि दूसरे विश्वयुद्ध के बाद ये साफ कहा गया था कि चीन के वो इलाके जो जापान के कब्जे में हैं उन्हें चीन को दोबारा वापस दे दिया जाएगा।

क्या है?

1. अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा बनाए गए विवादित द्वीपों पर जाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। ह्वाइट हाउस सामरिक तौर से महत्वपूर्ण द्वीपों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी जिम मैटी ने पिछले हफ्ते कहा कि दक्षिण चीन सागर के विवादित मुद्दों को कूटनीतिक तौर पर सुलझाने की जरूरत है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

2. चीन के विदेश मंत्री वैंग यी ने कहा कि वो अपने अमेरिकी दोस्तों को एक सलाह देते हैं। अमेरिकी दोस्तों को पहले 1943 के कायरो घोषणापत्र और 1945 में पॉटसडैम समझौते को पढ़ना चाहिए। उन समझौतों में साफ तौर पर ये लिखा गया है कि दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान जापान के कब्जे में जो द्वीप चले गए थे, उन्हें जापान वापस कर देगा। विवाद की जड़ में स्पार्टी आइलैंड है जिसे चीन नैंशा द्वीप के नाम से पुकारता है।
3. दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर अमेरिकी रक्षा मंत्री के बयान पर वैंग यी ने कहा कि चीन का स्पष्ट मत है कि विवादित मुद्दों को कूटनीतिक ढंग से सुलझाना चाहिए। उन्होंने कहा वैश्विक शांति हो या क्षेत्रीय स्तर पर शांति हो चीन कभी भी टकराव का रास्ता नहीं चुनता है। लेकिन चीन अपने संप्रभु अधिकारों का उचित तरीके से इस्तेमाल करता रहेगा।

चीनी पनडुब्बियों' पर नजर रखने का समझौता होगा अमेरिका के साथः

क्या भारत और अमेरिका मिलकर चीन की पनडुब्बियों पर नजर रखेंगे? अमेरिका की ओर से प्रस्तावित एक समझौता इसी सिलसिले में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि डॉनल्ड ट्रंप प्रशासन रक्षा संबंध बढ़ाने की खातिर इस पर साइन के लिए भारत पर जोर डालेगा, लेकिन भारत इसे साइन करने की जल्दी में नहीं है।

क्या है?

1. अमेरिका ने भारत से सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए 2004 में चार बेसिक समझौतों का प्रस्ताव रखा था। इनमें पहला 'एंड यूजर वेरिफिकेशन ऐंड मॉनिटरिंग अग्रीमेंट' काफी पहले साइन हो चुका है।
2. दूसरा LEMOA यानी 'लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट', जो 12 साल की बातचीत के बाद अब लागू होने जा रहा है।
3. बाकी दो हैं-कम्यूनिकेशंस कॉम्पैटिबिलिटी ऐंड सिक्यॉरिटी अग्रीमेंट (COMCASA) और बेसिक एक्सचेंज ऐंड कोऑपरेशन अग्रीमेंट (BECA)।
4. बताया जाता है कि COMCASA के तहत दोनों देशों की सेनाओं को सिक्युअर कम्यूनिकेशन की सुविधा हासिल होगी यानी अमेरिकी और भारतीय विमानों में लगे सेंसर और इक्विपमेंट आपस में डेटा शेयर कर सकेंगे। BECA के जरिये किसी खास लोकेशन का डेटा शेयर किया जा सकेगा।
5. रक्षा मंत्रालय का मानना है कि इन समझौतों का मकसद है दोनों देशों के सिस्टम में एक साथ ऑपरेट की क्षमता कायम करना। मंत्रालय के एक सूत्र ने बताया कि साथ ऑपरेट करने के लिए भारत को पहले वैसी कपैसिटी बनानी होगी।
6. यहां कुछ रक्षा जानकारों को लगता है कि बाकी के दो समझौते भारतीय सिस्टम में दखल दे सकते हैं। भारत सरकार की फंडिंग पाने वाले रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के डॉ. जी. बालचंद्रन का कहना है कि अमेरिका इन समझौतों से जुड़े उपकरणों को भारत को देने से पहले इन्हें साइन करने के लिए कह सकता है। लेकिन भारत फिलहाल इन समझौतों को साइन करने के पक्ष में नहीं है।
7. अमेरिका दलील देता रहा है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में चीन का दखल बढ़ रहा है। चीन की पाकिस्तान से दोस्ती जग जाहिर है और वह बांग्लादेश से भी संपर्क बढ़ा रहा है।
8. अमेरिकी पैसिफिक कमांड के कमांडर ऐडमिरल हैरिस बी. हैरिस का यह बयान पिछले महीने सुर्खियों में आ गया था कि COMCASA से दोनों देशों की नौसेनाएं दूसरों की पनडुब्बियों पर बेहतर तरीके से नजर रख सकेंगी। उनका इशारा चीनी पनडुब्बियों की ओर था।
9. भारत के पास P8I पनडुब्बी रोधी क्षमता वाले विमान हैं, जबकि हमारे पास P8A हैं। लेकिन दोनों सिस्टम मिलकर ऑपरेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के कम्यूनिकेशन सिस्टम अलग हैं। तब उन्होंने उम्मीद जताई थी कि भारत और अमेरिका के बीच ये दो पेंडिंग समझौते भी जल्द हो जाएंगे।

दक्षिण चीन सागर पर तैरते परमाणु संयंत्र बनाएगा चीनः

चीन आने वाले समय में दक्षिण चीन सागर में तैरते परमाणु संयंत्र विकसित करेगा। बीजिंग के मुताबिक, यह कदम विवादित समुद्री क्षेत्र के द्वीपों पर बिजली आपूर्ति बढ़ाने के लिए उठाया जा रहा है। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्री फॉर नेशनल डिफेंस के उप निदेशक वांग यिरेन ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समुद्री गैस के इस्तेमाल को बढ़ावा देने और समुद्रीय परियोजनाओं के लिए स्थायी ऊर्जा उपलब्ध करवाने की खातिर आगामी पांच वर्षो में चीन तैरते परमाणु प्लेटफॉर्म के विकास को प्राथमिकता देगा। वांग ने बताया कि चीनी अधिकारी संबद्ध मूलभूत तकनीकों और समुद्री परमाणु उर्जा संयंत्रों के मानकीकरण पर पहले ही शोध कर चुके हैं।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

क्या है?

1. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह देश की पंचवर्षीय आर्थिक विकास योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पिछले साल जुलाई में आधिकारिक वीचौट अकाउंट पर प्रकाशित लेख में चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के हवाले से बताया गया था कि भविष्य में चीन 20 तैरते परमाणु ऊर्जा स्टेशन विकसित कर सकता है।
2. ये संयंत्र दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर ऊर्जा और जल आपूर्ति में उल्लेखनीय इजाफा करेंगे।
3. नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के पूर्व अध्यक्ष सन क्विन ने मार्च 2016 में कहा था कि ये स्टेशन 2019 तक काम शुरू कर देंगे।
4. विशेषज्ञों के मुताबिक, तैरते संयंत्र प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में ज्यादा सुरक्षित होते हैं।
5. वर्तमान में चीन में 23 परमाणु ऊर्जा उत्पादन इकाइयां हैं। इनके अतिरिक्त 27 इकाइयां निर्माणाधीन हैं। निर्माणाधीन इकाइयों की संख्या पूरी दुनिया में निर्माणाधीन परमाणु इकाइयों की संख्या की एक तिहाई है।

आर्थिक

आम बजट खास बातें:

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने लोकसभा में आम बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा कि हम नीतिगत प्रशासन की ओर बढ़े हैं. हमारा ध्यान युवाओं की तरक्की पर है।

प्रमुख बिंदु

1. व्यक्तिगत आयकर के मामले में मध्यवर्ग को राहत देते हुए वित्तमंत्री ने ढाई से पांच लाख तक की आय पर लगने वाले 10 फीसदी कर को घटाकर पांच फीसदी कर दिया है।
2. 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक की आय वालों पर 10 फीसदी सरचार्ज लगाने की भी घोषणा की है, जबकि एक करोड़ से अधिक आय पर लगने वाले 15 फीसदी सरचार्ज को बरकरार रखा है।
3. साल 2017 में भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी में शामिल रहेगा।
4. देश में FDI भी बढ़ा है। भारत दुनिया की छठी सबसे बड़ी मैन्यूफैक्चरिंग इकोनॉमी है। पिछले एक साल में देश ने बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखे हैं। दो बड़े नीतिगत फैसले हुए। पहला-GST बिल पास हुआ और दूसरा नोटबंदी हुई।
5. किसानों को 10 लाख करोड़ के क्रेडिट का प्रावधान किया गया है। किसानों का 60 दिन का ब्याज माफ होगा। 40 फीसदी किसानों को कोऑपरेटिव सोसायटीज से क्रेडिट मिलेगा। फसल बीमा योजना में कवरेज को 40 फीसद बढ़ाया गया है।
6. मनरेगा के लिए 48 हजार करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसके तहत पांच लाख तालाब और बनाए जाएंगे।
7. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2016-17 में हर दिन 133 किलोमीटर सड़कें बनाई गई हैं जिसे बढ़ाया जाएगा।
8. नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनेगी जो हायर एजुकेशन के लिए सभी बड़े एंट्रेंस एग्जाम्स कराएगी। इससे सीबीएसई जैसी संस्थाएं एकेडमिक्स पर फोकस कर पाएंगी। 3.5 करोड़ युवाओं को मार्केट बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी।
9. 2019 तक 1 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
10. स्किल अवेयरनेस प्रोग्राम पर 4000 करोड़ खर्च होंगे। अच्छी क्वालिटी के इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे। स्वयं प्लेटफॉर्म बनाएंगे। इसमें 350 ऑनलाइन फैसिलिटीज होंगी।
11. सीनियर सिटीजन के लिए आधार बेस्ड स्मार्ट कार्ड बनेंगे जो उनकी सेहत का रिकॉर्ड रखेंगे।
12. वुमन और चाइल्ड वेलफेयर के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपये का प्रोविजन।
13. झारखंड और गुजरात में दो नए एम्स बनाए जाएंगे।
14. 2020 तक ब्रॉडगेज लाइन पर मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग खत्म कर दी जाएगी।
15. IRCTC से टिकट लेने पर सर्विस टैक्स को भी खत्म किए जाने की घोषणा की गई है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

बजट के लक्ष्य:

1. 2019 तक एक करोड़ परिवारों और 50 हजार ग्राम पंचायतों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला जाएगा। इसे पाने के लिए दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 में 4500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना (PMEGP) और क्रेडिट सपॉर्ट स्कीम के लिए तीन गुना आवंटन किया गया है।
2. एक मई 2018 तक देश के सभी गांवों तक बिजली पहुंचाने का दावा किया गया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत वर्ष 2017-18 के लिए सरकार ने 4814 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है।
3. उच्चा शिक्षण संस्थावओं के लिए सभी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करने के लिए स्वाघ्यत्तं और स्वो-संपोषित प्रमुख परीक्षा संगठन के रूप में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की स्थोपना का प्रस्ताव किया है। सीबीएसई, एआईसीटीई और अन्यर प्रमुख संस्थानों को इन प्रशासनिक उत्तपरदायित्वों से मुत्की कर दिया जाएगा, ताकि वे शैक्षिक कार्यों पर अधिक ध्यान दे सकें।
4. 2019 तक रेलवे की सारी कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया जाएगा। 2020 तक ब्रॉडगेज पर मानवरहित क्रॉसिंग खत्म। 3500 किमी की नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए एक लाख 31 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है।
5. 2019 तक एक करोड़ लोगों को पक्का घर देने का लक्ष्य बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लिए बजट अनुमान 2016-17 में आवंटित 15,000 करोड़ रुपये की धनराशि को बढ़ाकर बजट 2017-18 में 23,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
6. 2017 तक कालाजार और फाइलेरिया, 2018 तक कुष्ठक, 2020 तक खसरा और 2025 तक टीबी समाप्त करने के लिए कार्य योजना। सरकार 1.5 लाख स्वास्थ्य उप-केंद्रों को स्वास्थ्य और तंदरुस्ती केंद्रों में बदलेगी।
7. 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य। इसके लिए मार्च 2017 तक 10 लाख तालाब बनाए जाएंगे। मनरेगा के लिए 48000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह अबतक का सर्वाधिक आवंटन है।
8. वर्ष 2017-18 के अंत तक डेढ़ लाख ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर पर आधारित फास्ट इंटरनेट सुविधा। भारत नेट परियोजना को 10000 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव।
9. रोजगारपरक ट्रेनिंग के लिए प्रधानमंत्री कौशल केंद्रों का विस्तार 60 जिलों से बढ़ाकर 600 जिलों तक करने का लक्ष्य। 3. 5 करोड़ युवाओं को मार्केट की डिमांड के मुताबिक प्रशिक्षण। इसके लिए 4000 करोड़ रुपए की लागत से श्संकल्पश कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।
10. गांव स्तर पर महिला शक्ति केंद्र की स्थापना होगी। 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

PDS को नकदी रहित व्यावस्था पर लाने वाला पहला राज्य:

केन्द्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री राम विलास पासवान ने गुजरात राज्यं सरकार को देश में PDS को नकदी रहित व्यस्था पर लाने वाला पहला राज्य बनने पर बधाई दी। उन्हों ने इस बात पर भी प्रसन्नता व्यक्त की कि 31 मार्च, 2017 के निर्धारित लक्ष्य से बहुत पहले ही गुजरात ने अपने 17250 राशन की दुकानों पर आधार के माध्यम से भुगतान की व्यवस्था का संचालन प्रारम्भ कर दिया है।

क्या है?

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत मिलने वाला सस्ता राशन पाने के लिए अब लाभार्थियों को केवल आधार कार्ड का प्रयोग करना है। इससे लाभार्थी की पहचान होगी, दुकान स्तर पर होने वाला भ्रष्टाचार तथा अनाज की चोरी भी रुक सकेगी।
2. गुजरात में राज्य सरकार ने इससे भी आगे बढ़ते हुए सुविधा केन्द्र जो कि इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक विशेष पहल है, के साथ भागीदारी करते हुए इन दुकानों पर सुविधा केन्द्रों के माध्यम से मिलने वाली 30 डिजिटल सेवाओं को भी जोड़ लिया है।
3. अब उपभोक्ता को राशन दुकान से न केवल अनाज, बल्कि रेल, हवाई और बस यात्रा की टिकट भी मिल सकेगी। उपभोक्ता अपने मोबाइल के बिल का भुगतान भी इन दुकानों के माध्यम से कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त किसान अपनी

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

फसल की बीमा राशि, जीवन बीमा की राशि आदि का भुगतान भी इन केन्द्रों से कर सकेंगे। किसान Soil Health Card तथा अन्यि केन्द्रीकय योजनाओं में रजिस्ट्रेशन आदि की सुविधा भी इन केन्द्रों से प्राप्त कर सकेंगे।

4. राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को बस का पास तथा बिजली बिल के भुगतान आदि के लिए भी इन सुविधाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आम जनता कम्प्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्तस करने का कार्य भी अब राशन की दुकानों से ही प्राप्त कर सकती है।
5. देश भर में नकदी रहित व्यवस्था के लिए 19 जनवरी, 2017 को राज्यों के खाद्य मंत्रियों के साथ बैठक की थी, जिसमें अधिकांश राज्यों ने 31 मार्च, 2017 तक राशन दुकानों पर नकदी रहित व्यवस्थी करने का आश्वासन दिया था।
6. खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लगभग 81 करोड़ लाभार्थी हैं और मार्च, 2017 तक सभी राज्योंय द्वारा नकदी रहित प्रणाली अपनाने पर यह अपने आप में देश में सबसे बड़ी व्यवस्था हो जाएगी।

तकनीकी शिक्षा के लिए भारत ने किया समझौता:

देश में तीसरी तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के लिए भारत ने विश्व बैंक के साथ एक 201.50 लाख वित्तपोषण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में इस बात की जानकारी दी। इस परियोजना का उद्देश्य आठ पूर्वोत्तर राज्यों हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तराखंड और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रणाली की दक्षता में सुधार लाना है।

क्या है?

1. सरकार ने अब शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता और स्वायत्तता पर जोर देने की पहल की है। स्कूलों में हर साल इस बात का अलग से आकलन किया जाएगा कि अंक हासिल करने से इतर छात्र वास्तव में कितना कुछ सीख पा रहे हैं। इसी तरह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सभी तरह की प्रवेश परीक्षाओं को पारदर्शी और पेशेवर तरीके से आयोजित करने के लिए अलग से एक एजेंसी शुरू की जाएगी।
2. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट के दौरान कहा था कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार तेजी से सुधार करेगी। केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति घोषित करने जा रही है। इसमें भी प्रस्ताव किया गया है कि विश्वविद्यालय शिक्षा में आमूल बदलाव के लिए मौजूदा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया जाए।
3. गुणवत्ता वाले उच्च शैक्षणिक संस्थानों की प्रशासनिक और अकादमिक दोनों ही तरह की स्वायत्तता में बढ़ोतरी की जाएगी।
4. पहली बार देश में इंजीनियरिंग, मेडिकल जैसे उच्च शिक्षा के सभी पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए एक अलग एजेंसी का गठन किया जाएगा। यह राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी स्वायत्त संस्थान के तौर पर तो काम करेगी ही, अपना खर्च खुद वहन करेगी।

एनपीए के लिए 'बैड बैंक':

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की समस्या से जूझ रहे बैंकों की समस्या के समाधान के लिए एक 'बैड बैंक' की स्थापना की जा सकती है। वित्त मंत्री ने कहा कि 'बैड बैंक' या एक प्रकार के एसेट्स रिकंस्ट्रकशन कंपनी की स्थापना कर बैंकों की गैर निष्पादित परिसंपत्तियों को बाजार कीमत पर खरीद कर एनपीए की समस्या का समाधान किया जा सकता है।

क्या है?

1. जेटली ने बजट के बाद भारतीय उद्योग जगत के साथ बैठक में कहा, 'यह 'बैड बैंक' भी एक संभावित समाधान है। हम इस बारे में बोर्ड में चर्चा करेंगे।
2. आर्थिक सर्वेक्षण 2016-17 में एनपीए की समस्या से निपटने के लिए 'बैड बैंक' को स्थापित करने की सिफारिश की गई है।
3. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में नोटबंदी से संबंधित अध्यादेश 2016 की जगह लेने वाले विधेयक को लोकसभा में पेश किया।
4. इसमें 31 दिसंबर, 2016 के बाद पुराने 1000 और 500 रपये के नोटों को रखने, उनका लेनदेन करने या प्राप्त करने को प्रतिबंधित किया गया है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होगा पांच सब्सिडियरी बैंकों का विलय:

केंद्रीय कैबिनेट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उसकी पांच सब्सिडियरी बैंकों के विलय को मंजूरी दे दी है। इस अहम फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि महिला बैंक के विलय पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

गौरतलब है कि एसबीआई ने पिछले साल ही सब्सिडियरी बैंकों और भारतीय महिला बैंक को अपने साथ मिलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद उसने इस प्रपोजल को सरकार के पास भेजा था।

क्या है?

1. एसबीआई की पांच सहयोगी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद शामिल हैं।
2. इनमें स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर ऐंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर शेयर बाजार में लिस्टेड हैं। इन बैंकों के मर्जर के बाद जो एंटिटी बनेगी, उसके पास 37 लाख करोड़ का एसेट बेस और 50 करोड़ से अधिक कस्टमर्स होंगे।
3. एसबीआई ने 2008 में सहयोगी बैंक स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र को अपने साथ मिलाया था। इसके दो साल बाद उसने स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का मर्जर अपने साथ किया था।
4. एसबीआई ने हमेशा कहा है कि वह सहयोगी बैंकों को अपने साथ मिलाना चाहता है। हालांकि, कैपिटल की कमी के चलते वह अब तक ऐसा नहीं कर पाया था।
5. इन बैंकों की एंप्लॉयीज यूनियन भी मर्जर का विरोध कर रही हैं। सहयोगी बैंकों और भारतीय महिला बैंक को मिलाने के बाद एसबीआई का साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि वह दुनिया के बड़े बैंकों का मुकाबला कर सकेगा।
6. दिसंबर 2015 तक इस बैंक पास 22,500 ब्रांच और 58,000 एटीएम थे। अकेले एसबीआई की 16,500 ब्रांच हैं। उसकी 191 ब्रांच विदेश में हैं, जो 36 देशों में फैली हैं।

3 लाख से ज्यादा कैश लेने पर लगेगा 100% जुर्माना:

कालेधन पर लगाम लगाने की कोशिशों के बीच अब तीन लाख रुपये से अधिक का कैश स्वीकार करने वालों को भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इसकी शुरुआत एक अप्रैल से होगी। बजट 2017-18 में तीन लाख रुपये से अधिक के कैश लेनदेन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है। राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने कहा कि जो व्यक्ति जितनी राशि कैश में स्वीकार करेगा उसे उसके बराबर ही जुर्माना देना होगा।

क्या है?

1. यदि आप चार लाख रुपये कैश स्वीकार करते हैं तो आपको चार लाख रुपये का ही जुर्माना देना होगा। यह जुर्माना उस व्यक्ति पर लगेगा जो नकद स्वीकार करेगा। आप कैश में कोई महंगी घड़ी खरीदते हैं तो दुकानदार को यह टैक्स देना होगा। यह प्रावधान लोगों को बड़ी राशि के नकद लेनदेन से रोकने के लिए लाया गया है। नोटबंदी के बाद खातों में ब्लैक मनी आया है।
2. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने 2017-18 के बजट में आयकर कानून में धारा 269 एसटी जोड़ने का प्रस्ताव किया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में किसी एक व्यक्ति से एकल लेनदेन या किसी एक मामले अथवा मौके पर तीन लाख रुपये से अधिक की नकदी स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि, यह अंकुश सरकार, किसी बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत खातों या सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होगा।
3. प्रस्ताव में तीन लाख रुपये से अधिक की नकदी लेने वाले व्यक्ति पर जुर्माने का प्रावधान है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली मुख्यमंत्रियों की समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में एक सीमा से अधिक नकद लेनदेन पर रोक लगाने और 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर टैक्स लगाने की सिफारिश की थी।
4. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने 2017-18 के बजट में आयकर कानून में धारा 269 एसटी जोडने का प्रस्ताव किया। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में किसी एक व्यक्ति से एकल लेनदेन या किसी एक मामले अथवा मौके पर तीन लाख रुपये से अधिक की नकदी स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि, यह अंकुश सरकार, किसी बैंकिंग कंपनी, डाकघर बचत खातों या सहकारी बैंकों पर लागू नहीं होगा। अधिया ने कहा कि प्रस्ताव में तीन लाख रुपये से अधिक की नकदी लेने वाले व्यक्ति पर जुर्माने का प्रावधान है।
5. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली मुख्यमंत्रियों की समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में एक सीमा से अधिक नकद लेनदेन पर रोक लगाने तथा 50,000 रुपये से अधिक के भुगतान पर कर लगाने की सिफारिश की है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

भारत के लिए अमेरिका ने अपने निर्यात कानून में किया बदलाव:

भारत को बड़े रक्षा सहयोगी के तौर पर देखते हुए अमेरिका ने अपने निर्यात नियंत्रण कानूनों में आवश्यक परिवर्तन किया है जो भारत के लिए लाभदायक होगा। यह परिवर्तन भारत के हित में तो है ही साथ ही इससे रक्षा विभाग से जुड़ी भारतीय कंपनियों को भी लाभ होगा। साथ ही, दोनों देशों के बीच रक्षा तकनीक और हथियारों का आदान-प्रदान भी काफी आसान हो जाएगा।

क्या है?

1. अमेरिका के निर्यात नियंत्रण कानूनों में परिवर्तन के लिए लाए गए नए नियम के जरिए उन भारतीय कंपनियों को सुविधा दी गयी है जो कि अमेरिकी वाणिज्य विभाग के नियंत्रण वाले सैन्य सामानों का आयात करना चाहते हैं। नया नियम एक तरह से भारतीय कंपनियों को ऐसे आयातों की पूर्व स्वीकृति देता है।
2. इस नई व्यवस्था के तहत, बहुत मुश्किल से ही कभी ऐसा होगा कि भारत को सैन्य उपकरणों और हथियारों के आयात के लिए लाइसेंस न मिले।
3. नए नियम के कारण अब जिन कंपनियों को 'वैलिडेटेड ऐंड यूजर' का दर्जा मिल जाएगा, उन्हें हथियारों के आयात के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी।
4. USIBC के डिफेंस ऐंड एयरोस्पेस निदेशक बेंजामिन एस ने कहा, 'भारत में काम कर रहीं भारतीय और अमेरिकी कंपनियां नागरिक और सैन्य निर्माण, दोनों के लिए ही VEU का दर्जा आवंटित किए जाने का आवेदन कर सकती हैं। ऐसा करने के बाद उन्हें अलग से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ग्लोबल सप्लाइ चेन बनाने और बाजार की बदलती चुनौतियों पर तत्काल ध्यान देने के लिहाज से भी यह बहुत अच्छा कदम साबित होगा।'
5. पिछले 5 सालों के दौरान दोनों देशों के बीच 3 खरब रुपयों से अधिक की सैन्य तकनीक, हथियार और उपकरणों की खरीद हो चुकी है।
6. इसके लिए 810 लाइसेंस जारी किए गए। ज्यादातर लाइसेंस एयरोस्पेस सिस्टम विकसित करने और जमीन पर चलने वाले वाहनों की खरीद से जुड़े थे। इस बदली हुई व्यवस्था को भारतीय हितों के लिए काफी अच्छा माना जा रहा है।

विज्ञान और तकनिकी

भारतवंशी ने खोजा खारे पानी से पेयजल बनाने का सस्ता तरीका:

अमेरिका में भारतीय मूल के किशोर चौतन्य करमचेडू ने खारे पानी को स्वच्छ पेयजल में तब्दील करने का सस्ता और आसान तरीका खोज निकाला है। उसके इस शोध ने प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियों और विश्वविद्यालयों का ध्यान आकर्षित किया है।

क्या है?

1. ओरेगन के पोर्टलैंड में रहने वाले चौतन्य ने अपनी हाईस्कूल कक्षा में शुरू हुए विज्ञान के एक प्रयोग से पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा।
2. जेसुइट हाईस्कूल के इस छात्र ने कहा, 'मेरे पास दुनिया को बदलने की बड़ी योजना है।' हर आठ व्यक्ति में से एक के पास साफ पानी पीने की व्यवस्था नहीं है। यह एक गंभीर समस्या है जिसे दूर करने की जरूरत है।
3. धरती के करीब 70 फीसद हिस्से पर समुद्र है लेकिन इसका पानी खारा है। इससे पीने योग्य पानी बनाने का तरीका बेहद महंगा है। इसलिए यह इस राह की बड़ी समस्या है।
4. चौतन्य ने बताया कि उन्होंने सोखने वाले उच्च पॉलीमर के साथ परीक्षण कर समुद्र के पानी से नमक हटाकर साफ पेयजल बनाने का सस्ता तरीका ईजाद किया है।
5. स्कूल की बॉयोलॉजी शिक्षक डॉ लारा शमिह ने कहा कि मौजूदा तकनीक की तुलना में यह बेहद सस्ता है। इसकी पहुंच हर व्यक्ति तक हो सकती है।

ब्रह्मांड में पहली बार धरती के आकार वाले श्वेत तारे की खोज:

खगोलविदों ने ब्रह्माांड में पहली बार धरती के आकार वाले श्वेत वामन तारे (व्हाइट ड्वार्फ पल्सर) की खोज की है। व्हाइट ड्वार्फ पल्सर तारों की एक अवस्था है। इसमें तारा सिकुड़ जाता है और उसमें तेज रोशनी निकलती है। पृथ्वी से इस तारे की दूरी 380 प्रकाश वर्ष है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

क्या है?

1. ब्रिटेन की वारविक यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने नए तारे एआर स्कोरपी (एआर स्को) की पहचान पहले व्हाइट ड्वार्फ पल्सर के रूप में की है।
2. हालांकि पिंड के तौर पर इसका पता 1960 के दशक में ही लग गया था। तब इसे बेहद अलग तरह के पिंडों के साथ संबंद्ध किया गया था। इन्हें न्यूट्रॉन स्टार कहा जाता है। यह श्वेत वामन तारा आधी सदी से ज्यादा वक्त तक खगोलविदों के लिए अबूझ पहेली बना हुआ था।
3. शोधकर्ताओं ने बताया कि तारे का आकार पृथ्वी जितना है, लेकिन यह दो लाख गुना ज्यादा भारी है। यह एक ठंडे तारे की परिक्रमा करता है जिसमें उसे 3.6 घंटा लगता है। यह ठंडा तारा सूर्य का एक तिहाई है।

100 से अधिक नए ग्रहों की पहचानः

वैज्ञानिकों ने 100 से अधिक संभावित नए ग्रहों की पहचान की है। इनमें एक ग्रह एक तारे की परिक्रमा कर रहा है। यह ग्रह हमारी धरती से 8.1 प्रकाश वर्ष दूर है। इस खोज में एलियन की पहचान के लिए तैयार की गई तकनीक का उपयोग किया जा रहा है।

क्या है?

1. खगोलविद्ों ने इन ग्रहों की पहचान में रेडियल वेलोसिटी मेथड नामक तकनीक का इस्तेमाल किया है। यह सौर मंडल के बाहर तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज का अब तक सबसे बड़ा संग्रह है। इस विधि में इस तथ्य पर गौर किया गया कि ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण से तारे भी प्रभावित होते हैं।
2. खगोलविद इस तकनीक की मदद से ग्रह के गुरुत्वाकर्षण का तारे पर पड़ने वाले प्रभाव के चलते होने वाले कंपन की पहचान करने में सफल हुए।
3. यह डाटा दो दशक की अवधि वाले रेडियल वेलोसिटी प्लेनेट-हंटिंग प्रोग्राम के तहत एकत्र किया गया।
4. इस प्रोग्राम में हॉयर्स नामक स्पेक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे हवाई द्वीप के मौना में स्थित केक-1 टेलीस्कोप पर लगाया गया है।

विविध

प्राचीन खोया हुआ द्वीप मिलाः

हिंद महासागर के लोकप्रिय पर्यटक द्वीप मॉरीशस के नीचे एक खोए हुए द्वीप की मौजूदगी की वैज्ञानिकों ने पुष्टि की है। यह सुपर महाद्वीप गोंडवाना के टूटने के बाद संभवतः वहां बचा रह गया था। टूटने की यह प्रक्रिया करीब 20 करोड़ साल पहले शुरू हुई थी।

क्या है?

1. इस द्वीपीय टुकड़े को बाद में द्वीप पर हुए ज्वालामुखी विस्फोटों से निकले लावा ने ढक लिया। विशेषज्ञों का अनुमान है कि यह उस प्राचीन महाद्वीप का छोटा हिस्सा है, जो मैडागास्कर द्वीप से टूट कर बना होगा। यह घटना उस समय की बताई जाती है जब अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका अलग हुए और हिंद महासागर बना।
2. दक्षिण अफ्रीका में यूनिवर्सिटी आफ विटवॉटर्सरेंड के प्रोफेसर लेविस ऐशवाल ने बताया, हम महाद्वीपों के टूटने की प्रक्रिया का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि ग्रह के भूगर्भीय इतिहास को समझ सकें। ज्वालामुखी के लावे से बनी चट्टानों में मिले खनिज जिरकन का अध्ययन कर रहे ऐशवाल और उनकी टीम के मुताबिक इसके अवशेष मॉरीशस द्वीप से भी पुराने हैं।
3. उन्होंने बताया, धरती दो हिस्सों से बनी है, महाद्वीप जो कि पुराने हैं और महासागर जो कि नए हैं। महाद्वीपों पर चार अरब साल से अधिक पुरानी चट्टानें हैं, लेकिन आपको महासागरों में ऐसा कुछ नहीं मिलता क्योंकि यहां नई चट्टानें बनीं।
4. उन्होंने बताया, मॉरीशस एक द्वीप है और इस पर कोई भी चट्टान 90 लाख साल से अधिक पुरानी नहीं है। लेकिन द्वीप की चट्टानों के अध्ययन से हमने पाया कि जिरकन तीन अरब साल पुराना है।
5. जिरकन ऐसे खनिज हैं जो द्वीपों में ग्रेनाइट में मिलते हैं। इनमें यूरेनियम, थोरियम और सीसा के कण पाए जाते हैं। वे अपने भीतर भूगर्भीय प्रक्रियाओं का समृद्ध रिकॉर्ड समेटे हुए हैं और बेहद सटीक तरीके से इनके समय का पता लगाया जा सकता है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने लक्ष्य सेनः

उत्तराखंड के 15 वर्षीय लक्ष्य सेन जूनियर बैडमिंटन के पुरुष एकल वर्ग में दुनिया के नंबर 1 शटलर बन गए हैं। BFA की ओर से जारी जूनियर बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 10 खिलाड़ियों में लक्ष्य एकमात्र भारतीय हैं।

क्या है?

1. लक्ष्य ने 8 टूर्नमेंट खेलकर 16,903 अंक हासिल किए हैं, जबकि उनसे एक पायदान नीचे चीनी ताइपे के खिलाड़ी चिया हाओ ली के 16,091 अंक हैं। लक्ष्य 10 साल की उम्र से प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकैडमी में अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। इस किशोर खिलाड़ी की प्रतिभा को देखकर कोच प्रकाश पादुकोण खुद उनकी खास ट्रेनिंग का ध्यान रखते हैं।
2. विभिन्न स्तरों पर बैडमिंटन में शानदार प्रदर्शन के चलते लक्ष्य को अपनी बैडमिंटन प्रतिभा को और निखारने के लिए ओलिंपिक गोल्ड क्वीस्ट (ओजीक्यू) से भी मदद मिल रही है।
3. लक्ष्य के पिता डी.के. सेन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) में बैडमिंटन के कोच हैं। इसके अलावा उनके बड़े भाई चिराग सेन भी राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। BWF द्वारा जारी बैडमिंटन की इस जूनियर रैंकिंग में एशिया से 6 खिलाड़ी टॉप 10 में शुमार हैं।

महिला आरक्षण के मुद्दे पर सुलगा नागालैंडः

स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए प्रस्तावित 33 फीसद आरक्षण के ऐलान के बाद नागालैंड सुलग रहा है। आरक्षण के विरोध में कई नामी जनजातीय परिषदों के लोगों ने सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया था।इस हिंसा में दो लोगों की जान जा चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री टी आर जेलियांग के आवास का घेराव किया था। इन सबके बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर नागालैंड सरकार के महिला आरक्षण के फैसले पर इतना उग्र विरोध क्यों हो रहा है।

हिंसा के पीछे बड़ी वजहें

1. अर्बन लोकल बॉडी में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण देने का प्रस्ताव नागालैंड सरकार ने पेश किया है।
2. 2012 में नागा मदर्स संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की गई कि वो नागालैंड सरकार को अर्बन लोकल बॉडी में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण मुहैया कराने के लिये निर्देश जारी करे। अप्रैल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने नागा मदर्स संगठन के पक्ष में फैसला सुनाया।
3. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपालन में नागालैंड सरकार ने 16 साल से लंबित अर्बन लोकल बॉडी में चुनाव कराने का फैसला किया।
4. 2006 में नागालैंड की एक सशक्त जनजातीय परिषद ने अर्बन लोकल बॉडी में चुनाव कराए जाने का विरोध किया था। दरअसल उनकी शिकायत थी कि जिस आरक्षण व्यवस्था के तहत चुनाव कराए जाने थे उनमें सही ढंग से आरक्षण के बारे में जानकारी नहीं थी।
5. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नागालैंड सरकार ने अर्बल लोकल बॉडी में 33 फीसद महिला आरक्षण को पेश किया। लेकिन नागालैंड की कई जनजातीय परिषदों का कहना है कि ये प्रावधान अनुच्छेद 371। के तहत नागा लोगों को जो अधिकार मिले हैं उसका उल्लंघन हो रहा है।
6. ज्वाइंट कोआर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले कई जनजातीय परिषद एक फरवरी को होने वाले अर्बन लोकल बॉडी चुनाव का विरोध कर रही हैं।
7. 30 जनवरी को नागालैंड बैपटिस्ट काउंसिल ने नागालैंड सरकार और ज्वाइंट कोआर्डिनेशन कमेटी के बीच मध्यस्ता की। दोनों पक्षों के बीच बचाव का रास्ता ये निकाला गया कि जनजातीय परिषदें अपनी विरोध प्रदर्शन बंद कर देंगी और सरकार चुनावों को दो महीनों के लिए टाल देगी। लेकिन गुवाहाटी कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने चुनावों को टालने से इंकार कर दिया।
8. 31 जनवरी की रात में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक संघर्ष में दो लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद हिंसा और भड़क उठी। राज्य सरकार को ऐहतियात के तौर पर दीमापुर के कई इलाकों में क्रफ्यू लगाना पड़ा। कोहिमा में प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों में आग लगा दी।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

9. एक फरवरी को हालात को नियंत्रित करने के लिए नागालैंड सरकार ने सभी 12 अर्बन लोकल बॉडी में चुनाव कराने पर रोक लगा दी।
10. नागालैंड ट्राइबल एक्शन कमेटी(इस कमेटी में अलग-अलग जनजातीय परिषदें शामिल हैं) ने सीएम टी आर जेलियांग को शाम चार बजे तक इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया था। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने दीमापुर के पुलिस कमिश्नर को हटाने के साथ चुनाव को निरस्त करने की मांग की। लेकिन इन सबके बीच सीएम टी आर जेलियांग ने इस्तीफा देने से इंकार कर दिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की।

यूएन ने आतंकवाद विरोधी पैनल के लिए भारत से सदस्य मांगे:

संयुक्त राष्ट्र ने आतंकवाद विरोधी वैश्विक टीम के लिए भारत से अपने नामित व्यक्ति का नाम भेजने को कहा है। यह वैश्विक टीम आतंकवादी संगठनों और उसके प्रमुखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लेने वाली संयुक्त राष्ट्र की समिति की सहायता करेगी।

क्या है?

1. विश्व निकाय के आग्रह पर गृह और वित्त मंत्रालय को योग्य व्यक्ति का चुनाव करने को कहा गया है। चुने गए व्यक्ति का नाम वैश्विक टीम के लिए भेजा जाएगा।
2. पैनल में भारतीय सदस्य होने पर आतंकवाद के खिलाफ प्रयासों को बल मिलने की उम्मीद है। भारत को पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर पर शिकंजा कसने में मदद मिल सकती है।
3. मसूद अजहर को पिछले वर्ष पठानकोट वायुसैनिक अड्डे पर हुए आतंकवादी हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जाता है। भारत इस आतंकी सरगना और उसके संगठन को संयुक्त राष्ट्र की अल-कायदा और आइएस से जुड़े संगठनों और आतंकियों की प्रतिबंध सूची में शामिल कराना चाहता है। भारत के इस प्रयास में चीन हर बार बाधा उत्पन्न करता है।
4. वैश्विक टीम में योग्य व्यक्ति को नामित करने की मांग की गई है। नामित व्यक्ति विश्लेषणात्मक समर्थन और प्रतिबंध निगरानी टीम का सहयोग करेंगे। यह टीम 1267/1989/2253 आइएस और अल-कायदा प्रतिबंध समिति के लिए होगी। सूत्र ने कहा कि भारत ने पिछले वर्ष फरवरी में अपने नामित लोगों के नाम भेजे थे। लेकिन भेजे गए नाम में किसी को भी टीम में नहीं लिया गया।

लाल किला में मिले अंग्रेजों के जमाने के बम:

दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला स्थित कुएं की सफाई के दौरान अंग्रेजों के समय के बम बरामद हुए। इसके बाद बम को निष्क्रिय करने के लिये बम निरोधक दस्ते, अग्निशमन विभाग के अलावा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए।

क्या है?

1. पुरातात्विक विभाग के मजदूरों द्वारा कुएं की सफाई के दौरान ये बम मिले थे।
2. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हालांकि बम के विस्फोट होने की सम्भावना नहीं के बराबर है लेकिन कोई खतरा नहीं लिया जा सकता।
3. इससे पहले बीते साल अप्रैल में मेटकॉफ हाउस में खुदाई के दौरान अंग्रेजों के समय का बम मिला था जिसे एनएसजी ने निष्क्रिय किया था।

सहारा मामले पर SC सख्त:

सुप्रीम कोर्ट ने सेबी बनाम सहारा विवाद पर सुनवाई करते हुए सख्त आदेश सुनाया। कोर्ट ने पुणे स्थित एम्बी वैली को अपने कब्जे में लेने का आदेश दिया। साथ ही कहा कि शेष राशि जमा करने पर यह संपत्ति दोबारा सहारा को वापस कर दी जाएगी। सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया कि सेबी को 14,000 करोड़ रुपये का मूलधन वापस करना था, जिसमें से 11,000 करोड़ दिया जा चुका है। यह आदेश जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने दिया है।

क्या है?

1. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से अपनी संपत्ति की सूची सौंपने को कहा है। जिससे कि बकाया राशि वसूली जा सके। इस मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। सहारा ने जुलाई 2019 तक बकाया राशि देने की बात कही है।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

2. अगर 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपए जमा नहीं कराए गए तो उन्हें दोबारा जेल भेज दिया जाएगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा-सेबी विवाद मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सहारा को और समय देने से स्पष्ट इंकार कर दिया था।
3. पिछले सप्ताह सहारा समूह की तरफ से नई अर्जी दाखिल कर जल्द सुनवाई की दरख्वास्त की गयी थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर करते हुए आज की तारीख रखी थी।
4. सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह से निवेशकों के बकाया पैसे लौटाने का शेड्यूल देने को कहा था। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीरथ सिंह ठाकुर, जस्टिस रंजन गोगाई और एके सिकरी इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं।
5. सहारा प्रबंधन का कहना है कि निवेशकों को कुल 18,000 करोड़ रुपये लौटाए जा चुके हैं। शुरुआत में बेंच ने राय को 1000 करोड़ रुपये की रकम दो माह में सेबी को लौटाने को कहा था लेकिन बाद में रकम को कम कर 6 फरवरी, 2017 तक 600 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया।
6. सेबी ने पहले कहा था कि सहारा ग्रुप को ब्याज के साथ 37,000 करोड़ की रकम देनी होगी जिसमें मूल रकम 24,000 करोड़ रुपये थी। जिसमें से सहारा ने 10,918 करोड़ रुपये चुका दिया है।

2017 का पहला चंद्र ग्रहणः

साल 2017 का पहला चंद्र ग्रहण 11 फरवरी को सुबह 4 बजे लगने वाला है। वैसे तो यह एक खगोलीय घटना है, लेकिन बहुत से लोग इसे ज्योतिष और धर्म की नजर से भी देखते हैं और ग्रहण को अच्छा नहीं माना जाता। हालांकि साल का यह पहला चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्रग्रहण है जिस कारण इसका कोई खास प्रभाव नहीं होगा। लिहाजा इस चंद्र ग्रहण का सूतक भी मान्य नहीं होगा। 11 फरवरी को पड़ने वाला उपछाया चंद्र ग्रहण होगा जिसे खुली आंखों से नहीं देखा जा सकेगा। लेकिन खगोलविद टेलिस्कोप के जरिए इसे देख सकते हैं। चंद्र ग्रहण का प्रवेश 11 फरवरी की सुबह 4 बजकर 10 मिनट पर होगा। फरवरी 2017 में ही सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है जो 26 फरवरी को पड़ेगा। लेकिन यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा। नासा के मुताबिक भारत, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक, अंटार्कटिका के ज्यादातर हिस्सों में यह चंद्र ग्रहण नजर आएगा।

चंद्र ग्रहण से जुड़ी खास बातें:

1. चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को घटित हो सकता है।
2. चंद्र ग्रहण का प्रकार और अवधि चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करते हैं।
3. चंद्र ग्रहण को खुली आंखों से देखा जा सकता है क्योंकि इससे आंखों को नुकसान नहीं होता।
4. सूर्य ग्रहण की तरह ही चंद्र ग्रहण भी आंशिक और पूर्ण हो सकता है।

स्वना पांडया को अंतरिक्ष मिशन के लिए चुना गयाः

कनाडा में रहने वाली भारतीय मूल की चिकित्सक को नासा ने साल 2018 में होने वाले नागरिक विज्ञान अंतरिक्ष यात्री (सीएसए) कार्यक्रम के तहत अंतरिक्ष मिशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया है। अगर सब कुछ सही रहा तो 32 साल की डॉ स्वना पंड्या कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की लीग में शामिल हो सकती हैं। कनाडा में जन्मी डॉ पंड्या अलबर्टा विश्वविद्यालय अस्पताल के साथ एक सामान्य चिकित्सक है।

क्या है?

1. सीएसए कार्यक्रम में अच्छा स्कोर हासिल करने के बाद डॉ पांड्या को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। बचपन से ही डॉ पांडया में एक डॉक्टर और अंतरिक्ष यात्री बनने का जुनून था। वो एक ओपेरा गायक भी हैं। ताईकांडो में वो अंतरराष्ट्रीय चैंपियन रह चुकी हैं, साथ ही उन्होंने नौसेना सील के साथ मय थाई का प्रशिक्षण भी किया है।
2. पांडया ने अलबर्टा विश्वविद्यालय से न्यूरो साइंस में बीएसी की पढ़ाई की है। वहीं अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय से अंतरिक्ष विज्ञान में एमएससी की है।
3. इसके बाद उन्होंने अलबर्टा विश्वविद्यालय से चिकित्सा में एमडी की साथ ही उन्होंने एक ही समय में मेडिकल स्कूल के लिए आवेदन किया और अंतरिक्ष कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

कर्नाटक में आरक्षण कानून सुप्रीम कोर्ट ने किया रद:

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार के प्रमोशन में आरक्षण कानून को निरस्त कर दिया है। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इस अधिनियम में पर्याप्त प्रतिनिधित्व, पिछड़ापन और निपुणता के निर्धारित मानदंड का पालन नहीं किया गया। कोर्ट ने राज्य के श्कैच अपश नियम को भी बरकरार रखा है।

क्या है?

1. कर्नाटक सरकार के प्रोन्नति में आरक्षण कानून, 2002 के तहत कैच अप प्रावधान को खत्म कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले में कैच अप नियम को परिभाषित किया है।
2. इसके अनुसार, यदि सामान्य श्रेणी के वरिष्ठ कर्मचारियों को अनुसूचित जाति/जनजाति (एससी/एसटी) के कर्मचारियों से पहले प्रोन्नति मिलती है तो दोनों श्रेणियों के कर्मियों के समान स्तर में आने पर सामान्य वर्ग के कर्मचारियों की वरिष्ठता कायम रहेगी। कर्नाटक सरकार ने कानून बनाकर इस प्रावधान को खत्म कर दिया था।
3. कर्नाटक हाई कोर्ट ने इसे उचित ठहराया था। राज्य के कर्मचारियों ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
4. जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने राज्य कानून के इस प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और 16 (सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता) का उल्लंघन करार दिया।
5. कोर्ट ने कहा कि 85वें संविधान संशोधन के तहत राज्यों को प्रमोशन में आरक्षण का तौर तरीका निर्धारित करने का अधिकार है। हालांकि, इस तरह का फैसला लेने से पहले उसे पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव, पिछड़ापन और निपुणता के मापदंडों का पालन जरूरी है। कर्नाटक सरकार के कानून में इसको ध्यान में नहीं रखा गया। कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया।

संयुक्त सातवें स्थान के साथ सर्वश्रेष्ठ भारतीय रहे लाहिड़ी:

भारत के नंबर वन गोल्फर अनिबार्ण लाहिड़ी चौथे और आखिरी राउंड में चार अंडर 68 का कार्ड खेलने के बाद 30 लाख डॉलर की बैंक गोल्फ चौंपियनशिप में संयुक्त सातवें स्थान के साथ सर्वश्रेष्ठ भारतीय रहे। लाहिड़ी ने चार राउंड में 69, 68, 69 और 68 के स्कोर किए। उनका कुल स्कोर 14 अंडर 274 रहा। पैराग्वे के फेब्रिजियो जानोटी ने नौ अंडर 63 का जबर्दस्त कार्ड खेला और 19 अंडर 269 के स्कोर के साथ खिताब ले उड़े। जानोटी को इस जीत से पांच लाख डॉलर की पुरस्कार राशि मिली।

लाहिड़ी के हिस्से में 82500 डॉलर आए। अन्य भारतीयों में देश के उभरते स्टार शुभंकर शर्मा (69) ने 12 अंडर 276 के स्कोर के साथ संयुक्त नौंवा स्थान हासिल किया। राशिद खान (69) और शिव कपूर (70) नौ अंडर 279 के स्कोर के साथ संयुक्त 12वें स्थान पर रहे। गगनजीत भुल्लर (72) को आठ अंडर 280 के स्कोर के साथ संयुक्त 20वां, चिराग कुमार (71) को चार अंडर 284 के स्कोर के साथ संयुक्त 41वां और ज्योति रंधावा (71) को पार 288 के स्कोर के साथ संयुक्त 59वां स्थान मिला।

एच1बी वीजा बिल ने बढ़ाई भारतीयों की चिंता:

अमेरिका के सिलिकॉन वैली में काम करने वाले भारतीय मूल के आइटी पेशेवरों में एच।बी वीजा को लेकर चिंता बढ़ गई है। इस पर ट्रंप प्रशासन अमेरिकी कांग्रेस में नया विधेयक पेश करने जा रहा है। पेशेवरों ने कहा कि इसका भारतीय समुदाय पर प्रतिकूल असर पड़ना लगभग तय है।

क्या है?

1. हाल ही में सैकड़ों भारतीय पेशेवर सिलिकॉन वैली में जमा हुए और इस पर अपनी चिंता जाहिर की। उनका कहना था कि इस मुद्दे पर सांसदों और नीति निर्माताओं के बीच जागरुकता पैदा करने की जरूरत है। ग्लोबल इंडियन टेक्नोलाजी प्रोफेशनल एसोसिएशन के अध्यक्ष खंडेराव कंद ने कहा, श्हम किसी भी दुरुपयोग को रोकने वाले कदम का समर्थन करते हैं।
2. हालांकि ज्यादातर विधेयकों में न्यूनतम वेतन में वृद्धि को साधा जाता है। इसका प्रतिकूल असर अमेरिकी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाले भारतीय छात्रों पर पड़ेगा। इसका उन कुशल पेशेवरों पर भी असर पड़ेगा जिनके पास कुछ साल का ही अनुभव है। इनके लिए नौकरी पाना बेहद कठिन हो जाएगा।'

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

3. एच1बी एक गैर प्रवासी वीजा है। इससे अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारी रखने की इजाजत मिलती है। इसके लिए हर साल हजारों कर्मचारियों के लिए कंपनियां इस वीजा पर निर्भर होती हैं। एसोसिएशन की बैठक में इस बात की सिफारिश की गई कि नीति निर्माताओं और उद्योग जगत की बड़ी हस्तियों के बीच जागरुकता पैदा की जाए।

एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार पर लगाया जुर्माना:

उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क में वन्य जीवन के संघर्ष और ग्रामीणों के पुनर्वास को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्तराखंड सरकार और संबंधित विभागों पर जुर्माना लगाया है। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अगुवाई वाली बेंच ने याचिका पर जवाब न देने पर राज्य के अधिकारियो को लताड़ा भी है। इसके साथ ही एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार, वन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, मुख्य वनसंरक्षक और पौड़ी गढ़वाल के एसएसपी पर 20000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

बता दें कि पिछली सुनवाई पर एनजीटी ने राज्य सरकार से राजाजी नेशनल पार्क में पुनर्वास को लेकर दायर अपील पर जवाब मांगा था। जवाब देने के लिए राज्य सरकार ने एक सप्ताह का समय लिया था, लेकिन तय समय में सरकार के जवाब न देने पर एनजीटी ने यह कड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि ग्रीन पैनल उत्तराखंड निवासी मदन सिंह बिष्ट की अपील पर सुनवाई कर रहा है। याची ने राजाजी नेशनल पार्क में रह रहे ग्रामीणों के पुनर्वास को लेकर याचिका दायर की थी।

SC में दी लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश की उस याचिका का विरोध किया जिसमें आधार विधेयक की धन विधेयक के रूप में समर्थन किए जाने के लोकसभा अध्यक्ष के फैसले को चुनौती दी गई है। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने वरिष्ठ अधिवक्ता पी चिदंबरम की दलीलों का विरोध किया। चिदंबरम याचिकाकर्ता रमेश की ओर से पेश हुए थे।

क्या है?

1. चिदंबरम ने कहा कि राज्यसभा के समक्ष विचार से बचने के लिए आधार विधेयक का समर्थन धन विधेयक के रूप में किया, जिसे धन विधेयक पर कोई अधिकार नहीं होता है। हालांकि, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अध्यक्ष के फैसले को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है और इसके अतिरिक्त विधेयक में संविधान के तहत सभी आवश्यक जरूरतें शामिल हैं जो कि धन विधेयक के रूप में समर्थन के लिए जरूरी होती हैं क्योंकि समाज कल्याण कार्यक्रमों पर आधार से जुड़ा प्रत्येक व्यय समेकित कोष से निकाला जाएगा।
2. आधार विधेयक को धन विधेयक के रूप में समर्थन किए जाने के अध्यक्ष के फैसले की समीक्षा पर जोर देते हुए चिदंबरम ने कहा कि यह देखना महत्वपूर्ण है कि किसे धन विधेयक के रूप में समर्थना किया जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति एनवी रमण की पीठ का मत था कि याचिका में उठाया गया मुद्दा गंभीर है।
3. हालांकि, इसने अटॉर्नी जनरल की इस बात से सहमति जताई कि यह मुद्दा समेकित कोष से धन निकालने से जुड़ा है। पीठ ने चिदंबरम से कहा कि वह अटॉर्नी जनरल द्वारा उठाई गई सभी आपित्तयों को देखें। पीठ ने मामले को यह कहते हुए चार हफ्ते के लिए टाल दिया कि वह मुद्दे पर तुरंत संज्ञान नहीं लेना चाहती।
4. आधार (वित्तीय एवं अन्य रियायत, लाभ एवं सेवा का लक्षित वितरण) विधेयक 2016 पिछले साल मार्च में चर्चा के बाद लोकसभा में पारित किया गया था। यह विधेयक 16 मार्च को राज्यसभा में लाया गया था जहां इसमें कई संशोधन किए गए थे।
5. जब पीठ ने पूछा था कि क्या यह (आधार को धन विधेयक के रूप में लेना) न्यायिक समीक्षा के दायरे में आता है तब अटार्नी जनरल ने कहा था कि रमेश के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है अतएव संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर उनकी याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता। चिदम्बरम ने कहा था कि आधार विधेयक को धन विधेयक के तौर पर नहीं लिया जा सकता, अतएव याचिका अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गयी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने पीठ से कहा था कि इस विधेयक को लोकसभा ने ध्वनिमत से पारित तो किया था लेकिन जब राज्यसभा के सभापति से शिकायत की गयी थी तब उन्होंने कहा था कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अभिप्रमाणित विधेयक पर कोई कदम उठाने का उन्हें अधिकार नहीं है।
6. पीठ ने तब कहा था कि यह एक गंभीर मामला है एवं उस पर उपयुक्त सुनवाई की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने रमेश की अर्जी पर 25 मई, 2016 को इस मामले में रोहतगी से मदद मांगी थी लेकिन कोई नोटिस नहीं जारी किया था। लोकसभा ने 16 मार्च को आधार विधेयक पारित किया था जिसका लक्ष्य आधार विशिष्ट पहचान के माध्यम से सब्सिसी का उचित

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

लाभार्थियों तक पहुंचना है। सदन ने राज्यसभा के पांच संशोधनों की सिफारिशों को खारिज करने के बाद लोकसभा ने आधार (वित्तीय एवं अन्य रियायत, लाभ एवं सेवा का लक्षित वितरण) विधेयक 2016 को ध्वनिमत से पारित किया था।

फर्जी कंपनियों के मामले में कोलकाता शीर्ष पर:

इस बार आम बजट में फर्जी कंपनियों के खिलाफ नियमों को सख्त बनाने का प्रस्ताव है। बीते हफ्ते ही प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस मुद्दे को लेकर टास्क फोर्स गठित किया गया है। अब इस नए नियम व सख्ती का सबसे ज्यादा खामियाजा कोलकाता को भुगतना पड़ सकता है। दरअसल, एक ही पते पर रजिस्टर्ड ज्यादातर कंपनियों की सर्च के मामले में पूरे देश में कोलकाता शीर्ष पर है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, महानगर में 9/12, लालबाजार स्ट्रीट के पते पर इस समय कुल 315 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। संयोग से यह लालबाजार स्थित कोलकाता पुलिस के मुख्यालय का पता भी है। सूत्रों के अनुसार कॉरपोरेट ड्यू डिलिजेंस में विशेषज्ञता हासिल करने वाली एक एनालिटिक्स फर्म ने जब कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों को खंगाला तो पता चला कि 9/12, लाल बाजार स्ट्रीट के पते पर जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं. उनमें से 84 कंपनियां सिर्फ एक ब्लॉक के रूम नंबर 10 में हैं। यह इलाका चार्टर्ड एकाउंटेंट का ठिकाना भी है और ऐसी ज्यादातर कंपनियां प्राइवेट लिमिटेड हैं, जो होलसेल ट्रेडिंग और रियल एस्टेट से जुड़ी हैं।

क्या है?

1. रिपोर्ट के मुताबिक महानगर में कुल 11,281 से भी ज्यादा कंपनियां 148 पतों पर रजिस्टर्ड हैं। यानी औसतन एक पते पर 76 कंपनियां कागजों पर चल रही हैं। 9/12, लाल बाजार स्ट्रीट के अलावा 52 वेस्टर्न स्ट्रीट, ग्रोर्की टेरेस, 266, दक्षिणदारी रोड, शेक्सपीयर सरणी और 4ए पॉलित स्ट्रीट जैसे कुछ ऐसे पते हैं, जिन पर सबसे ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं।
2. इस बावत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि ऐसी कई कंपनियों का वजूद सिर्फ काले धन को सफेद बनाने के लिए है। एक सूत्र ने बताया कि निश्चित तौर पर ये फर्जी कंपनियां हैं, जिनका मकसद अवैध धन को ठिकाने लगाना है।
3. कॉरपोरेट मंत्रालय के अलावा उसके अधीन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (एसएफआइओ) और आयकर विभाग ऐसे चलन से वाकिफ है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इधर, इस बारे में पूछे जाने पर कोलकाता के एक नामी वकील का कहना है कि एक पते ही कितनी कंपनियां रजिस्टर्ड कराई जा सकती हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। उनके मुताबिक, कंसल्टेंट आमतौर पर कंपनियों का रजिस्टर्ड हाउस रखते हैं, जिसके लिए वे कंप्लायंस का काम देखते हैं। सिंगापुर और मॉरीशस में यह चलन आम है। सिंगापुर में एक कंपनी सेक्रेटरी फर्म सैकड़ों कंपनियों के रजिस्टर्ड ऑफिस का ठिकाना होता है, जिसे आमतौर पर लेटर बॉक्स कंपनियां कहा जाता है।
4. आपको बता दें कि इससे पहले साल 2013 में पश्चिम बंगाल में जब हजारों करोड़ रुपये के सारधा चिटफंड घोटाले का खुलासा हुआ था, उस दौरान भी जांच में पता चला था कि एक ही पते पर सारधा ग्रुप की दर्जनों कंपनियां रजिस्टर्ड थी। अभी भी सीबीआइ, ईडी व एसएफआइओ इस मामले की जांच कर रही है।

ट्रिपल तलाक के कानूनी पहलुओं पर देंगे फैसला: सुप्रीम कोर्ट:

ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह निकाह हलाला और बहुविवाह की प्रथा के कानूनी पहलुओं पर फैसला करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह मुस्लिम लॉ के तहत तलाक पर विचार नहीं करेगा। कोर्ट ने सभी पक्षों से कहा है कि वह 16 फरवरी तक तय कर ले कि किन मुद्दों पर सुनवाई होगी।

क्या है?

1. चीफ जस्टिस जेएस खेहर, जस्टिस एनवी रमणा और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि ट्रिपल तलाक का मामला मानवाधिकारों से जुड़ा मामला है और वह ट्रिपल तलाक के मामले में सुनवाई करेंगे समान नागरिक संहिता (कॉमन सिविल कोड) के मुद्दे पर सुनवाई नहीं करेंगे।
2. मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह तीन तलाक की वैधता से जुड़ी याचिकाओं पर 11 मई तक फैसला देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वह विशेष केस के तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार नहीं करेगा और वह सिर्फ कानूनी मुद्दे देखेगा।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)

3. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक, निकाह हलाल और कई शादियों जैसी प्रथाओं का विरोध किया था। लैंगिक समानता और महिलाओं के मान सम्मान के साथ समझौता नहीं हो सकता और भारत जैसे सेक्युलर देश में महिला को जो संविधान में अधिकार दिया गया है उससे वंचित नहीं किया जा सकता।
4. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने केंद्र सरकार की दलीलों का विरोध किया था। उसने इसे मुस्लिमों के मामलों में दखल करार दिया था। इसके अलावा एक और मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने भी कोर्ट से कहा था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखल नहीं दिया जाना चाहिए।

हरियाणा में कैंसर के सर्वाधिक मरीजः

फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एफएमआरआइ) के मुताबिक 2014 में कैंसर के मरीज हरियाणा में सबसे ज्यादा सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली और फिर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। एफएमआरआइ ने दिल्ली और गुरुग्राम के अस्पतालों में आने वाले मरीजों पर सर्वे के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है।

क्या है?

1. एफएमआरआइ की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में 15664 कुल कैंसर के मरीजों में 2157 (13.8 फीसद) नए मरीज आए। इनमें 1191 (55.2 फीसद) पुरुष और 966 (44.8 फीसद) महिला मरीज हैं।
2. पुरुष कैंसर पीड़ितों की औसत उम्र 54 साल, जबकि महिलाओं की 52.4 साल पाई गई। सबसे ज्यादा मरीज हरियाणा के 39.6 फीसद, उसके बाद दिल्ली के 27.3 फीसद और उत्तर प्रदेश के 12.7 फीसद मरीज रजिस्टर्ड किए गए।
3. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् (आइसीएमआर) के मुताबिक देश में कैंसर मौत का सबसे बड़ा कारण है। 2020 तक कैंसर के नए मरीजों की संख्या 17.3 लाख तक पहुंच जाएगी। भारत में कुल मौतों में से 53 फीसद लोग कैंसर के कारण मरते हैं जबकि विश्व में छह फीसद लोग कैंसर के कारण दम तोड़ रहे हैं।
4. एफएमआरआइ का मानना है कि तंबाकू के सेवन के कारण 23.4 फीसद पुरुष और 8.8 फीसद महिलाएं कैंसर की गिरफ्त में जा रहे हैं। पुरुषों में सबसे ज्यादा फेफड़ों का कैंसर (31.2 फीसद) हो रहा है, जबकि महिलाओं में यह 36.5 फीसद है।
5. इसके अलावा बच्चे भी कैंसर की चपेट में आ रह हैं। 2013 से 2014 तक तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक कुल मरीजों में 5.8 फीसद बच्चे भी कैंसर से पीडिघ्त पाए गए।
6. इनमें लड़कियों की संख्या 4.9 फीसद और लड़कों की 6.6 फीसद है। एफएमआरआइ के कार्यकारी निदेशक विनोद रैना ने कहा कि रिपोर्ट तैयार करना मुश्किल भरा काम था।

KSG – (DELHI VN) 9717380832, (DELHI RN) 9811293743, (JAIPUR) 8290800441, (BHOPAL) 7509975361, (PATNA)